लखनऊ

शनिवार, 05 अक्टूबर, 2024

वर्ष : 10 । अंक: 85

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

किसी दिन, जब आपके सामने कोई समस्या ना आए-आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। -स्वामी विवेकानंद

TODAY WEATHER

DAY 33° Hi

NIGHT 27° Low

संक्षेप

नसरल्लाह के बाद अब हमास कमांडर पर निशाना, इजराइली एयर स्ट्राइक में 18 लोगों की मौत

तेल अवीव। इजराइल ने गुरुवार देर रात वेस्ट बैंक के तुलकरम में एयर स्ट्राइक कर दिया। जिसके बाद फिलिस्तीनी प्राधिकरण के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में पश्चिमी तट पर हुए सबसे घातक हवाई हमलों में से एक में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। इजराइल रक्षा बलों और शिन बेट की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा कि हमले में तुलकरम में हमास के शीर्ष कमांडर जही यासर अब्द अल-रजेक औफी के साथ-साथ कई अन्य आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। सेना के अनुसार, औफी आतंकी हमले की योजना बना रहा था। बयान में कहा गया है कि ओफी ने ही पिछले महीने अटेरेट बस्ती के पास कार बम विस्फोट हमले की योजना बनाई थी और उसका नेतृत्व किया था। सेना के अनुसार, वह अन्य आतंकवादी गुर्गों को हथियार उपलब्ध कराने में भी शामिल था, जिन्होंने हाल ही में पश्चिमी तट और इजराइल में कई हमले किए, जिनमें इजराइली नागरिक भी घायल हुए। आईडीएफ ने कहा कि औफी ने हमास की ओर से आतंकवादी नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम किया। फिर क्षेत्र में आतंकवादी गुर्गों को गोलीबारी और विस्फोटक हमले करने में सहायता की। आईडीएफ ने कहा कि उसका इरादा तत्काल समय सीमा में हमला करने का था और इसलिए उसको निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने पिछले साल पश्चिमी तट पर दर्जनों हवाई हमले किए थे। लेकिन ये हमले अधिकतर ड्रोन और हेलीकॉप्टरों से थे। गुरुवार के हमले में 18 फिलिस्तीनियों की मौत के अलावा कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। फिलिस्तीनी सुरक्षा सेवाओं के एक सूत्र ने बताया कि यह हमला साल 2000 के बाद से पश्चिमी तट पर सबसे घातक हमला है।

भारत के 80 प्रतिशत घरों पर 'ड्रैगन' की नजर, डेटा एक्सपोजर का बढ़ा खतरा! चौंका देगा नया सर्वे

वॉशिंगटन। भारत में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के मार्केट पर चीन का बड़ा कब्जा है। आज देश के लगभग सभी घरों में मेड इन चाइना प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसकी वजह से ड्रैगन का खतरा भी बढ़ा है। हालांकि हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने की मांग की थी। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर कई बार चाइनीज प्रोडक्ट बायकाट का ट्रेंड भी चलता रहता है, लेकिन इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देता। दरअसल, एक सर्वे ने मेड इन चाइना प्रोडक्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस सर्वे में यह बताया गया है कि 79 प्रतिशत भारतीय परिवारों के पास एक या अधिक मेड इन चाइना गैजेट हैं, जिसकी वजह से उन पर सर्विलांस का खतरा मंडरा रहा है। वहीं 37 प्रतिशत लोग इन प्रोडक्ट्स से जुड़े ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं, जिससे डेटा ट्रांसमिशन का भा जोखिम बढ़ गया है। सर्वे के मुताबिक 25 प्रतिशत घरों में एक या उससे ज्यादा मेड इन चाइना गैजेट मौजूद हैं। वहीं सर्वे में शामिल किए गए 54 प्रतिशत घरों में तीन से ज्यादा मेड इन चाइना डिवाइस हैं। इन डिवाइस से जुड़े चाइनीज ऐप फोटो और वीडियो जैसे यूजर डाटा को स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए चीन भेज रहे हैं।

युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है कांग्रेस: अमित शाह

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली में छापेमारी के बाद 5,600 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 500 किलोग्राम से अधिक कोकीन बरामद की, जिसे राष्ट्रीय राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी नशीली दवाओं का भंडाफोड़ कहा जा रहा है। नशीली दवाओं के भंडाफोड़ के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। भाजपा ने लगाया कि ड्रग कारोबार से जुड़े 5,600 करोड़ रुपये की जब्ती के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी को भारतीय युवा कांग्रेस की दिल्ली इकाई के सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है।

अब एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर वार किया है। अमित शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा कि एक ओर जहाँ मोदी सरकार 'नशामुक्त भारत' के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की ₹5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ, वह सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है।

भाजपा नेता ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार, ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना, ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर 'नशामुक्त भारत' बनाने के लिए संकल्पित है। भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने देश को बर्बाद करने में शामिल मादक पदार्थ तस्करों से कथित संबंधों को लेकर कांग्रेस की आलोचना की और मुख्य विपक्षी पार्टी से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या मादक पदार्थों के पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस अपने प्रचार में कर रही है और क्या पार्टी का, कथित सरगना तुषार गोयल के साथ संबंध कारोबार तक भी है?

त्रिवेदी ने दावा किया कि गोयल की न केवल के सी वेणुगोपाल और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीरें हैं बल्कि उनके पास हुड्डा का मोबाइल नंबर भी है। उन्होंने कहा कि हुड्डा परिवार को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने मीडिया के समक्ष दिल्ली युवा कांग्रेस के आरटीआई सेल के प्रमुख के रूप में गोयल की नियुक्ति का पत्र पढ़ा और दावा किया कि इसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी उल्लेख है।

सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जा सकते

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के बारे में आलोचनात्मक लेखन के लिए पत्रकारों पर आपराधिक मामला नहीं दर्ज किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मामले सिर्फ इसलिए नहीं थोपे जाने चाहिए क्योंकि उनके लेखन को सरकार की आलोचना माना जाता है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ उपाध्याय की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने पत्रकारिता लेख को लेकर यूपी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने मामले को 5 नवंबर के लिए पोस्ट कर दिया।

मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ऐसी खौफनाक थी टक्कर, उछलकर नाले में गिरा ट्रक का टायर, 10 लोगों की मौत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गुरुवार देर रात एक ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिर्जापुर के SP अभिनंदन ने बताया कि यह दुर्घटना देर रात करीब एक बजे मिर्जापुर-वाराणसी सीमा पर कछवां और मिर्जामुराद के बीच जीटी रोड पर हुई। एसपी ने बताया, ''ट्रैक्टर-ट्रॉली में 13 मजदूर थे जो भदोही जिले में निर्माण कार्य करके लौट रहे थे, तभी उनके वाहन को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया।'' सूचना मिलते ही एसपी अभिनंदन और अन्य अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

अपनों से मिलने घर लौट रहे थे मजदूर

दुर्घटना कछवा थाना क्षेत्र के कछवा मिर्जामुराद जीटी रोड पर रात करीब 1 बजे के आस पास की है। बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर पर 13 लोग सवार होकर जनपद भदोही से वाराणसी की तरफ जा रहे थे। थाना कछवा क्षेत्र के कछवा मिर्जामुराद जीटी रोड पर पीछे से एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। ट्रैक्टर सवार 13 लोगों में से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का टायर निकलकर दूर नाले में जा गिरा। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य करते हुए घायलों को इजाल के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी भिजवाया। ट्रैक्टर सवार सभी लोग मजदूर थे जो जनपद भदोही से छत ढलाई का काम कर के अपने घर मिर्जामुराद वाराणसी जा रहे थे।

क्या बोले अधिकारी?

पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 10 मजदूरों की मौत हो गई। तीन घायल हैं, जिनको वाराणसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। भदोही से मजदूर काम कर वाराणसी जा रहे थे। ट्रकचालक मौके से फरार हो गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने साधा भाजपा पर निशाना

'2 लाख पक्की नौकरियां देगी कांग्रेस सरकार'

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने एक्स पोस्ट के जरिए हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी, अपराध और नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने विजय संकल्प यात्रा के दौरान लोगों के साथ अपने अनुभव और बातचीत साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' का सहारा लिया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई गई बेरोज़गारी की बीमारी ने हरियाणा की जड़ों, युवाओं के भविष्य और प्रदेश की सुरक्षा को गहरे संकट में डाल दिया है।

राहुल ने हरियाणा के निवासियों के साथ अपनी बैठकों का विवरण दिया, जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान घर की बनी रोटियाँ साझा कीं और उन्हें राज्य की जटिल समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की फैलाई बेरोज़गारी की बीमारी ने हरियाणा की जड़ों, युवाओं के भविष्य और प्रदेश की सुरक्षा को गहरे संकट में डाल दिया है। हरियाणा की कुछ बहनों ने विजय संकल्प यात्रा के दौरान आश्रय दिया, बहुत प्यार से घर की रोटी खिलाई और साथ ही प्रदेश की जटिल समस्याएं समझाईं। आज, भारत में सबसे अधिक बेरोज़गारी हरियाणा में है। इसका कारण है - भाजपा ने एक दशक में प्रदेश के युवाओं को रोज़गार देने वाली हर प्रणाली की रीढ़ तोड़ दी है।

राहुल ने अपने पोस्ट में दावा किया कि गलत GST और नोटबंदी से छोटे व्यापारों की कमर तोड़ दी। अग्निवीर से सेना की तैयारी करने वाले युवाओं का हौंसला तोड़ा। काले कानूनों से कृषि व्यापार करने वालों की हिम्मत तोड़ी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि खिलाड़ियों से समर्थन छीनकर उनका सपना तोड़ा। परिवार पहचान पत्र से सरकारी भर्ती रोककर परिवारों को तोड़ा। इसका असर बताते हुए उन्होंने कहा कि नशे के गिरफ्त में युवा हुनर बर्बाद हो रहा है। निराश नौजवान अपराध की राह पकड़ रहे हैं। डंकी जैसे खतरों के सफर से तबाह होते परिवार। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में आने वाली कांग्रेस सरकार 2 लाख पक्की नौकरियों की भर्ती करेगी और हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी। हरियाणा की बहनों को वचन दिया है कि इस तबाही को रोकूंगा, उनके बच्चों की रक्षा करूंगा - रोज़गार वापस आएगा, और हर परिवार खुशहाल होगा।

कोई त्रुटि नहीं, एससी/एसटी के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले की समीक्षा से SC का इनकार

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार देने वाले संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्य एससी श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटा के भीतर अलग कोटा देने के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।

इसके बाद फैसले के खिलाफ कई समीक्षा याचिकाएं दायर की गईं। न्यायालय ने यह कहते हुए फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया कि इसमें कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। बेंच ने आदेश में कहा कि समीक्षा याचिकाओं को पढ़ने के बाद, रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए, समीक्षा याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने फैसला सुनाया। अपनी एकमात्र असहमति में, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने कहा कि अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

बहुमत वाले छह न्यायाधीशों में से चार ने अनुसूचित जाति से 'क्रीमी लेयर' को बाहर करने की आवश्यकता के बारे में विस्तृत टिप्पणियाँ कीं और कहा कि सरकार को उनकी पहचान करने के लिए कदम उठाने चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण की अनुमति देते समय, राज्य किसी उप-वर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। साथ ही, राज्य को उप-वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर उप-वर्गीकरण को उचित ठहराना होगा।

मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप, युद्धग्रस्त पश्चिम एशिया में भारतीयों की भर्ती की सुविधा दे रही मोदी सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार का कौशल विकास सहयोग पश्चिम एशिया युद्ध में इजरायल में लगभग 15,000 भारतीय श्रमिकों की भर्ती की सुविधा प्रदान कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि पहले रूस-यूक्रेन युद्ध में जाने के लिए देश के युवाओं को संदिग्ध एजेंटों द्वारा धोखा दिया गया था और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच मोदी सरकार की राष्ट्रीय कौशल विकास सहयोग इजरायल में लगभग 15,000 भारतीय श्रमिकों की भर्ती में जुटी है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा कि इससे पहले कई भारतीय युवाओं को रूस-यूक्रेन युद्ध में जाने के लिए संदिग्ध एजेंटों द्वारा धोखा दिया गया था, और कई युवाओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। यह मोदी सरकार की युवा विरोधी नीतियों के कारण पैदा हुई बेलगाम बेरोज़गारी का नतीजा है। ये तथ्य कि अकुशल, अर्ध-कुशल और शिक्षित युवा अपनी जान जोखिम में डालकर युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तथाकथित उच्च वेतन पर काम करने के लिए तैयार हैं, यह बताता है कि नौकरियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े-बड़े दावे उनकी विफलताओं को छिपा नहीं सकते !

कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा के युवा जो इन युद्ध क्षेत्रों में नौकरी की तलाश करने के लिए मजबूर हैं, कल वोटिंग के दौरान भाजपा को करारा सबक सिखाएँगे! लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि हरियाणा की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस रोजगार सृजन पर जोर देगी तथा राज्य को नशामुक्त किया जाएगा जिससे हर परिवार खुशहाल होगा। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई गई बेरोज़गारी की बीमारी ने हरियाणा की जड़ों, युवाओं के भविष्य और प्रदेश की सुरक्षा को गहरे संकट में डाल दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीट के लिए शनिवार को मतदान होगा और मतगणना आठ अक्टूबर को होगी।

वोटिंग आज, 1027 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर, 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ। और जननायक जनता पार्टी ने राज्य में सरकार बनाई और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी (जेजेपी), आम आदमी पार्टी (आप) और इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। एकल चरण वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शनिवार, 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम लगभग 6 बजे समाप्त होगा। कुल 1,031 उम्मीदवार 90 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं जिनमें 101 महिलाएं हैं। इन उम्मीदवारों में 464 निर्दलीय लड़ रहे हैं। मतदान के लिए कुल 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस एक दशक के बाद सरकार में वापसी की उम्मीद कर रही है। प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (लाडवा), विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला-किलोई), इनेलो के अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद), कांग्रेस की विनेश फोगट (जुलाना) शामिल हैं।

सात साल से भाजपा सरकार सड़कों के गड्ढे नहीं भर पायी : अखिलेश यादव

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में गड्ढा मुक्त के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और लूट हुई है। इस सरकार में विकास कार्य ठप्प है। बजट के पैसे का बंदरबांट हो रहा है। सात साल से भाजपा सरकार सड़कों के गड्ढे. नहीं भर पायी। हर साल गड्ढा मुक्त करने के नाम पर हजारों करोड़ रूपये का बजट जारी होता है। फिर उसकी लूट हो जाती है। सड़के जसकी तस रह जाती है। सड़कों के गड्ढों के कारण प्रदेश में हर दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इस सरकार में अब तक कई लोग सड़कों के गड्ढों के कारण मौत के मुंह में जा

चुके हैं। अभी इसी बुधवार को गाजीपुर जिले में गड्ढे में जाने से असंतुलित हुई मोटर साइकिल से गिरने से महिला की मौत हो गयी। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पूरी तरह नकारा साबित हुई है। आम जनता बेबस है। भाजपाई और ठेकेदार इसे अवसर मानकर जश्न मनाते है। गड्ढ़ामुक्त के नाम पर हजारों करोड़ का बजट जारी होता है। जो ऊपर से नीचे तक बंट जाता है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। इस सरकार में हो रहे हर निर्माण कार्य में भारी लूट हो रही है। भाजपा की इस झूठ और लूट की सरकार में सड़कों के गड्ढे. लोगों की निरन्तर जान ले रहे है। मुख्यमंत्री जी ने अब तक अपने पूरे कार्यकाल में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के नाम पर न जाने कितनी बार तारीख दे चुके है लेकिन भ्रष्ट सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। जो बजट जारी होता है सब मिलकर डकार जाते हैं। मुख्यमंत्री के आदेश कागज पर सीमित और बेअसर है।

यूपी में 2014 से तीन गुनी हो गई भाजपा के मुस्लिम सदस्यों की संख्या! चौंकाने वाली रिपोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश में अपने चल रहे अभियान के जरिए मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर करने की कोशिश में लगी है। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां मुस्लिम वोट पारंपरिक रूप से पार्टी से दूर जाता रहा है। भाजपा के आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर, 2024 तक 4.12 लाख से अधिक मुस्लिम पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये आंकड़ा 2014 में पिछले अभियान से तीन गुना अधिक है, जब लगभग 1.25 लाख मुस्लिम सदस्य बने थे। सदस्यता में इस उछाल को एक बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, खासकर यह देखते हुए कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को ऐतिहासिक रूप से भाजपा विरोधी मतदाता आधार माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की कम सीटों की संख्या को रणनीतिक मुस्लिम वोटिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि अभियान तेज होने के कारण राज्य में मुस्लिम सदस्यों की संख्या जल्द ही 5 लाख को पार करने की उम्मीद है। अली ने कहा कि अब बीजेपी कार्यकर्ता घर-घर जाएंगे और मुस्लिम परिवारों से मिलकर हमारी पहुंच को और बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान का दूसरा चरण, जो 17 सितंबर से शुरू हुआ, 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का दस्तावेज है – '...लोगों का काम है कहना'

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। 'लोगों का काम है कहना...' पुस्तक का आखिरी पन्ना पलटते समय संयोग से महात्मा गांधी का एक ध्येय वाक्य मन–मस्तिष्क में गूंज उठा – 'कर्म ही पूजा है'। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो बार–बार महात्मा गांधी का ये वाक्य सहसा अंतर्गन में सफर कर रहा था। ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बापू के इस विचार को चरितार्थ उस शख्सियत ने किया है जिनके जीवनवृत्त पर ये पुस्तक लिखी गई है। प्रो. (डॉ) संजय द्विवेदी भारतीय मीडिया जगत में सुपरिचित और सुविख्यात नाम हैं। वरिष्ठ पत्रकार और मीडियाकर्मियों के लिए ये नाम इसलिए जाना–पहचाना है क्योंकि संजय जी अनथक मीडिया के विभिन्न आयामों के जरिये सक्रिय रहते हैं। पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए यह नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि पत्रकारिता के विद्यार्थी संजय जी को मीडिया गुरु कहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने देखा है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा प्रभारी कुलपति की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए भी विद्यार्थियों को बतौर शिक्षक पढ़ाना उनकी दैनंदिनी रही थी। इसीलिए प्रो. (डॉ) संजय द्विवेदी देशभर में पत्रकारिता के कुनबे की हर पीढ़ी में एक पत्रकार, एक शिक्षक, एक लेखक, एक विश्लेषक, एक विचारक और मीडिया गुरू के रूप में सम्मान के साथ याद किये जाते हैं।

प्रो. (डॉ) संजय द्विवेदी पर एकाग्र पुस्तक 'लोगों का काम है कहना...' उनके व्यक्तित्व के साथ ही कृतित्व पर मूलतः आधारित है। पुस्तक में देश के 14 मूर्धन्य विद्वानों द्वारा द्विवेदी जी के विचारों, उनके लेखकीय और प्रशासकीय यात्रा का जिस तरह से वर्णन किया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि अपने जीवन का एक–एक क्षण पत्रकारिता और लेखन को समर्पित कर देना संजय जी का मानो एकमात्र लक्ष्य हो। वैसे, प्रो. द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित यह पहली पुस्तक नहीं है। इससे पहले 'कुछ तो लोग कहेंगे', 'संजय द्विवेदी का सृजन संसार' और 'जो कहूंगा सच कहूंगा' प्रकाशित हो चुकी हैं और इन पुस्तकों को मीडिया के मोहल्ले में खूब सराहा भी गया।

'...लोगों का काम है कहना' शीर्षक अपने आप में प्रो. द्विवेदी के विचारों को सु-स्पष्ट करता है। मैं पुस्तक के संपादक लोकेन्द्र सिंह को बधाई दूंगा कि उन्होंने यह शीर्षक चुना। यह शीर्षक ही अपनेआप में एक बड़ा अध्याय या कहूं कि किताब की तरह है, जो कि प्रो. द्विवेदी के जीवनवृत्त को उजागर करता है। प्रो. द्विवेदी के व्यक्तित्व से स्पष्ट झलकता है कि वे अपने काम में सदैव मगन होकर, व्यर्थ में एक क्षण गवाएँ बिना अपने लेखन कार्य के माध्यम से देश तथा समाजहित में सदैव कार्यरत रहते हैं। 'कुछ तो लोग कहेंगे या लोगों का काम है कहना' – ये विचार आदरेय संजय जी का जीवन दर्शन है, क्योंकि ये कहने की जिम्मेदारी उन्होंने लोगों को देकर रखी है। यही कारण भी है कि वे डेढ़ दशक से अधिक समय पत्रकारिता में सक्रिय रहे। राजनीतिक और मीडिया संदर्भों पर अबतक लगभग 3 हजार से अधिक आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव तथा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति, कुलसचिव तथा दस वर्षों तक जनसंचार विभाग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निभाया। इसके साथ ही भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के महानिदेशक रहे। अबतक विभिन्न विषयों पर 11 पुस्तक प्रकाशन एवं 21 पुस्तकों का संपादन तथा उनके व्यक्तित्व पर 4 पुस्तकों का प्रकाशन उनकी पत्रकारिता की सतत जारी साधना के फलसफें बयां कर रही है। कुल 156 पृष्ठों की यह पुस्तक प्रो. संजय द्विवेदी जी के जीवनवृत्त के जरिये पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए पठनीय, प्रेरणा के दस्तावेज की तरह है। पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में प्रो. द्विवेदी जी की अक्षर साधना अनवरत रहे तथा वे पत्रकारिता की नवपौध के प्रेरणापुरुष रहें, यही कामना है। शेष ...लोगों का काम है कहना।

पुस्तक-चर्चा-

पुस्तक - ...लोगों का काम है कहना

संपादक –लोकेन्द्र सिंह

प्रकाशक – यश पब्लिकेशंस, नई दिल्ली

मूल्य – 350/- मात्र

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अमृतकाल मे सहभागिता कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को गहनाग देव संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गहनाग राय पट्टी, विकासखंड अमानीगंज अयोध्या में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित 'आइये रोजगार करें' प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अमृतकाल सहभागिता समारोह में शामिल हुये।

उप मुख्यमंत्री जी का आगमन अन्तर्राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या पर हुआ, जहां महापौर अयोध्या महंत गिरीश पति त्रिपाठी, संजीव सिंह व उपनिदेशक समाज कल्याण ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। तत्पश्चात उप मुख्यमंत्री ने गहनाग बाबा के मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया एवं ग्राम चैपाल में डा0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा स्वयं सहायता समूहो केक्षकार्यक्रम में सम्मिलित हुये, जहां स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किये जा रहे दीपोत्सव के दीयों का अवलोकन किया गया। अगले चरण में उप मुख्यमंत्री समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन में पहुंचे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) समाज कल्याण असीम अरुण उपस्थित रहे। समारोह में मंत्री गणों ने पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, अग्रणी बैंक प्रबन्धक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, स्वयं सहायता समूह आदि विभागों द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया तथा श्रीमती शीला देवी ग्राम प्रधान को उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रमाण पत्र, 01 लाभार्थी को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्रशस्ति पत्र तथा 09 लाभार्थियों को अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति का डमी चेक, आश्रम पद्वति के 06 मेधावी छात्रों को प्रशंसा पत्र, आयुष्मान कार्ड के 04 लाभार्थियों को डमी चेक, पीएम आवास योजना के 05 लाभार्थियों को चाभी, पीएम किसान सम्मान निधि के 02 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर के 01 लाभार्थी को 24 लाख का चेक व 200 बी0सी0 सखी को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये कहा कि आज गहनाग बाबा की पावन धरा पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जनपद अयोध्या में केंद्र एवं प्रदेश सरकार के द्वारा चहुंमुखी विकास हो रहा है इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन योजना के तहत नियमित राशन दिया जा रहा है तथा आयुष्मान योजना के तहत गरीब वर्ग के व्यक्तियों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ ही ग्राम की समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार आपके द्वार (गांव की समस्या गांव में समाधान) चैपाल के माध्यम से त्वरित, गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बी0सी0 सखी के माध्यम से लखपति दीदी योजना को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करते हुए गरीबों को बैंक की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, किसान सम्मान निधि, आवास योजना, वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि लाभार्थीपरक योजनाओं के माध्यम से सभी पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्ष ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है तथा इसके लिए ग्राम पंचायतों में खुली बैठक करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जीरो टालरेन्स की नीति के तहत अपराधियों पर अंकुश लगा रही है तथा युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए सेवायोजन के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है। कहा कि हर शुक्रवार को आयोजित होने वाले 'ग्राम चैपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान' में ग्राम चैपाल में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किया और ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए उनकी समस्याओं को एक-एक करके सुना और त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) समाज कल्याण असीम अरुण ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री त्र के नेतृत्व में प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास की भावना के तहत कार्य कर रही है।

इस अवसर पर मा विधायक रूदौली रामचंद्र यादव, एमएलसी अवनीश पटेल, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, पूर्व सांसद लल्लू सिंह सहित अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।

जनपद अयोध्या में (खिहारन) के अजीत मौर्य जी के भाई रंजीत मौर्य जी के निधन की सूचना प्राप्त हुई थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को उनके आवास पहुंच कर उनके स्मृति चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें : प्रमुख सचिव

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटीएलायन्स इंडिया व ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर के साझा प्रयास द्वारा राज्य स्तरीय राउंडटेबल कान्फ्रेंस का आयोजन लखनऊ के एक होटल में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों यथा स्वास्थ्य, समाज कल्याण, बाल एवं महिला कल्याण, पुलिस, न्याय, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, यौनकर्मी व प्रबुद्ध समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह राउंडटेबल विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक महत्वपूर्ण आदेश पर केंद्रित रहा जो यौनकर्मियों के मूलभूत अधिकारों की बात करता है। मई 2022 में जारी इस आदेश में स्पष्ट रूप से यौनकर्मियों के जीवन, उनकी गरिमा और कानून के समक्ष समानता के अधिकारों को मान्यता दी गई है। इसका उद्देश्य यौनकर्मियों के अधिकारों, उनकी गरिमा और कल्याण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करना और प्रभावी रणनीति तैयार करना था ताकि राज्य में यौनकर्मियों को भेदभाव और हिंसा से सुरक्षा मिल सके।

प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बतौर मुख्य अथिति कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे ख़ुशी है कि उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी, एलाइंस हेल्थ और सेक्स वर्कर एसोसियेशन द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण कान्फ्रेंस में सभी सम्बंधित विभाग शामिल हुए है इस कान्फ्रेंस की सफलता इसी में है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गये निर्देशों में उल्लेखित सभी 7 प्रमुख बिन्दुओं पर कार्ययोजना बना कर सभी विभाग इनको अमल में लाने के प्रयास करते हुए सेक्स वर्कर के सम्मान और अधिकारों को दिलाने में सहयोग करें। उन्होंने इस बात जोर दिया कि कार्यक्रम के अंत में एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाये ताकि सभी डिपार्टमेंट इस पर काम करें । इस कान्फ्रेंस को रस्मअदाएगी न मान कर असल में काम करने की एक रणनीति बनाने के लिए उपयोग किया जाए है ।

राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने बताया कि यौनकर्मियों के लिए एचआईवीएड्स की रोकथाम और उपचार के लिए व्यापक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब यौनकर्मी बिना किसी भय या भेदभाव के इन सेवाओं का उपयोग कर सकें। हमने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और समाज कल्याण विभाग को भी आमंत्रित किया ताकि यौनकर्मियों की आजीविका तक पहुँच बन सके । ये सभी बातें निचले स्तर तक जायें ताकि हम बेहतर समाज बन सके ।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) डीडीजी प्रिवेंशन से सोभिनी ने बताया कि भारत में 24 लाख लोग एचआईवी से पीड़ति है। इनके लिए नाको के 904 प्रोजैक्ट्स एचआईवी जागरूकता पर चलायें जा रहे है । अगर हम बात करें कोविड के समय की तो सबसे ज्यादा इनकी ही आजीविका प्रभावित हुई ऐसे में नाको की तरफ से उन्हें ड्राई राशन वितरित किया गया । साथ ही अच्छी बात यह है कि प्रावधान है जिसमें नाको के गैजेट्स ऑफिसर बिना किसी अन्य जानकारी के आधार कार्ड बना सकते है। सेक्रेटरी सालसा संतोष कुमार ने कहा कि यौनकर्मी समाज के एक संवेदनशील वर्ग का हिस्सा हैं और यह हमारा नैतिक और कानूनी दायित्व है कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी सहायता और सामाजिक सुरक्षा का पूरा लाभ मिले। उन्होंने कहा कि यौनकर्मियों के अधिकारों का सम्मान करना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना राज्य का दायित्व है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यौनकर्मियों को उनके पेशे के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए। ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स से पुतुल कहा कि केवल नीतियों का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन नीतियों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यौनकर्मियों के प्रति पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के व्यवहार में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। यह देखा गया है कि पुलिस और यौनकर्मियों के बीच संबंध कई बार तनावपूर्ण रहे हैं, और इसे बदलने के लिए पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाना आवश्यक है।

डग्गामार वाहनो के विरुद्ध चला अभियान, दो लग्जरी कार हुई सीज

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुलतानपुर। रोडवेज बस स्टाप, पयागीपुर और अमहट चैराहा डग्गामारी के लिए जाना जाता है, प्रभावी कार्यवाही ना होने के चलते डग्गामारी का धंधा फल-फूल रहा है। लगातार शिकायतों के बाद कभी-कभी यातायात विभाग का हंटर चल ही जाता है, शुक्रवार को प्रातः यातायात निरीक्षक राम निरंजन हमराहियों संग बस स्टाप पहुचें, जहां एक डग्गामार अर्टिगा कार सवारियां भर रही थी, टीआई ने सीधी कार्यवाही करते हुए सीज कर दिया। बस स्टाप से अमहट चैराहे पहुंचने से पहले डग्गामारों को भनक लग गई, मौके से डग्गामार खिसक लिए। बावजूद इसके एक अर्टिगा कार यातायात टीम के हांथ लग ही गई, टीम ने बगैर देर किये उक्त कार को सीज कर यार्ड में भेज दिया। यातायात पुलिस की कार्यवाही से डग्गामारी करने वालो में हडकंप मचा हुआ है।

मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय को उपकरण मुहैया कराएं प्राचार्य : कमिश्नर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुलतानपुर। मण्डलायुक्त अयोध्या मण्डल अयोध्या गौरव दयाल ने जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना, पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा व मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वैशाली चोपड़ा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ जनपद भ्रमण के दूसरे दिन नवनिर्मित जिला चिकित्सालय सुलतानपुर, राजकीय मेडिकल कालेज सुलतानपुर, जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत निर्मित वि0ख0 दूबेपुर में दाहाफिरोजपुर ग्राम पंचायत पेयजल परियोजना (पानी की टंकी), पेयजल पाइप लाइन, पशुचिकित्सा विभाग की वृहद अण्डा उत्पादन इकाई अवध पोलैट्री फार्म केनौरा, वि0ख0 लम्भुआ सुलतानपुर का निरीक्षण किया ।

मण्डलायुक्त अयोध्या मण्डल अयोध्या द्वारा सर्वप्रथम नवनिर्मित जिला चिकित्सालय सुलतानपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय में निर्मित कुल 06 भवनों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला चिकित्सालय में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग अयोध्या निर्माण खण्ड-2 द्वारा कराये गये कार्यों यथा- फर्श पर टाईलीकरण, फालसीलिंग, लाइटिंग, वाटर सप्लाई लीकेज, पेयजल, ड्रैनेज सिस्टम आदि की गुणवत्ता को चेक किया गया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कहा कि वाटर सप्लाई सिस्टम कहीं पर भी लीक नहीं होना चाहिये, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। इसी प्रकार उन्होंने कार्यदायी संस्था को कई आवश्यक सुझाव दिये। उन्होंने मेडिकल कालेज प्राचार्य सलिल श्रीवास्तव को निर्देशित करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सभी मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराकर चिकित्सालय को संचालित किया जाये, जिससे आम जनमानस को लाभ मिल सके। तत्पश्चात मण्डलायुक्त ने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों के साथ नवनिर्मित राजकीय मेडिकल कालेज दूबेपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एकेडमिक ब्लॉक, बॉयज हॉस्टल, गल्स हॉस्टल, प्रधानाचार्य कक्ष, डाइनिंग ब्लॉक, मल्टीपरपज हॉल, ऑटोप्सी, बाउण्ड्रीवाल का निरीक्षण किया गया। आयुक्त महोदय द्वारा क्लारूम निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित से तकनीकी जानकारियाँ प्राप्त की गयी। वहां उपलब्ध कराये गये मेडिकल उपकरण आदि की गुणवत्ता को भी जॉचा-परखा गया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी भवनों की वाटर सप्लाई लाइन को विशेष तौर पर चेक किया जाये, कहीं पर भी लींकेज न रहे। इसी प्रकार उन्होंने प्राचार्य राजकीय मेडिकल कालेज को निर्देशित किया कि कार्यदायी संस्था को समय-समय पर सभी जानकारियां उपलब्ध कराते रहें, जिससे छोटी-छोटी कमियों को समय से दूर किया जा सके। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओ0पी0 चैधरी, एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार पाण्डेय, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार सहित कार्यदायी संस्था के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दवा सप्लायर माफिया के शिकंजे में स्वास्थ्य विभाग

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

मीरजापुर। जनपद में स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा ड्रग माफिया वर्तमान में सक्रिय है, जो सीबीआई द्वारा आरोपित है और उसके ऊपर मुकदमे की चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। उक्त माफिया कंपनी के संचालकगण सुरेंद्र पांडे एवं महेंद्र पांडे एसके डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से अपने कंपनी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में दवाओ एवं स्वस्थ्य उपकरणों की सप्लाई का काम फर्जी तरीके से करते हैं। जिनमें सिर्फ कागजों पर ही सप्लाई होती है। दवाओ की कोई सप्लाई नहीं होती है। जिनमें स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके वरिष्ठ लिपिक और स्वास्थ्य विभाग का पूरा एक जाल बना हुआ है जो भ्रष्टाचारियों का गैंग के रूप में सक्रिय हैं। उक्त एसके डिस्ट्रीब्यूटर्स वाराणसी फर्म द्वारा मिर्जापुर जनपद में एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) में व्यापक पैमाने पर फर्जी बिल वाउचर लगाकर बिना दवा सप्लाई किया ही करोड़ों रुपए की दवा का सप्लाई दिखा दिया गया है। और उनके साथ इस भ्रष्टाचार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएल वर्मा तथा स्थानांतरित कनिष्ठ सहायक अमित कुमार सिंह की मिली भगत है। जिससे यह गैंग सरकार को करोड़ो रुपए का चुना लगा रहा है। उक्त फर्म द्वारा बिना दवा सप्लाई की ही फर्जी बिल वाउचर बनाकर करोड़ों रुपए के समान का सप्लाई लिखा गया है। उक्त फर्म द्वारा पूर्व में भी इसी तरह की फर्जी सप्लाई दिखाई गई थी जिसमें जांच में सीबीआई द्वारा मुकदमा करके चार्ज शीट भी दाखिल की जा चुकी है । उक्त फर्म और उक्त फर्म की दोनों संचालक सुरेंद्र पांडे एवं महेंद्र पांडे पर वित्तीय गबन का आरोप है। यह इस आरोप में तिहाड़ जेल भी जा चुके हैं बावजूद इसके मिर्जापुर जनपद द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इन्हें परमिट दिया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में यह दवा सप्लाई करें। परंतु दवा सप्लाई नहीं हुई। बल्कि करोड रुपए का फर्जी दवा कागज पर ही सप्लाई कर दिया गया। उक्त फर्म के दोनों संचालक 2010 में तिहाड़ जेल में भी निरुद्ध हो चुके हैं और अपने फर्जी बिल वाउचर के आधार पर यह दोनों 10 करोड़ के लगभग का टर्नओवर रखते हैं। उक्त धोखाधड़ी वह फर्जी सप्लाई की बात जब जनता में छनकर आई तो वरिष्ठ समाजसेवी मिर्जापुर सेवा समिति के संयोजक दिलीप सिंह गहरवार एडवोकेट ने अपर निदेशक स्वास्थ्य व विभिन्न अधिकारियों के यहां सारे मामले की शिकायत की।। जिसमें स्वास्थ्य विभाग में सक्रिय गैंग ने एक फर्जी रिपोर्ट क्लीन चिट देकर बनाई जिसमें अपर निदेशक स्वास्थ्य ने आईजीआरएस की शिकायत का निस्तारण करने के लिए 17 सितंबर 2024 को शिकायतकर्ता को बुलाया जबकि उक्त लेटर 03 अक्टूबर को रिसीव कराया जा रहा है, ताकि शिकायतकर्ता अपने साक्ष्य को ना रख सके । और उससे पहले ही उक्त लोग फर्जी तरीके से गबन करने वाले फर्म को क्लीन चिट दे दी जाए। शिकायतकर्ता दिलीप सिंह गहरवार एडवोकेट द्वारा दवाओं के सप्लायर व दवा माफिया तथा सीबीआई द्वारा आरोपित उक्त फॉर्म के संचालक सुरेंद्र पांडे एवं महेंद्र पांडे के फर्म के नियमितताओं के संबंध में प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग दो लखनऊ मुख्यमंत्री तथा सचिव स्वास्थ्य को भी पत्र लिखा गया है। जिसके प्रकाश में उक्त जांच अपर निदेशक स्वास्थ्य को सौंप गई थी। परंतु उन्होंने आरोपियों को बचाने के लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएल वर्मा व लिपिक जो वर्तमान में स्थानांतरित होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग में जमे हुए हैं अमित कुमार सिंह, की मदद से शिकायतकर्ता को जानबूझकर अपना साक्ष्य रखने के लिए पूर्व का समय देकर लगभग 15 दिन बाद पत्र रिसीव कराया गया।

डीएम की अध्यक्षता में पिपराड़ाड़ में ग्राम चौपाल का किया गया आयोजन

मीरजापुर। भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार के क्रम में जनपद के ग्राम पिपराड़ाड़, परगना कंतित, तहसील सदर में ग्राम चैपाल पूर्व सूचना एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के उपरान्त जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। जिसमें अपर जिलाधिकारी (भू राजस्व), उप संचालक चकबन्दी सत्य प्रकाश सिंह व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी नरेन्द्र सिंह व चकबन्दी अधिकारी, अतुल प्रकाश यादव व सहायक चकबन्दी अधिकारी सुबोध कुमार सिंह, चकबन्दीकर्ता व चकबन्दी लेखपाल आदि अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। ग्रामीणों व काश्तकारों ने चैपाल में अपनी समस्याओं को सक्षम अधिकारीगण के सामने रखा। जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।

भूखे जरूरतमंदों फ्री भोजन उपलब्ध कराना महान और पुनीत कार्य : सरदार बलदेव सिंह

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुलतानपुर। स्वासाशी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय/जिला अस्पताल और रेलवे स्टेशन परिसर में इलाज करा रहे मरीजों और उनकी देखभाल कर रहे तीमारदारों, यात्रियों तथा जरूरतमंदों को शुद्ध पौष्टिक गरम ताजा मुफ्त भोजन संघ द्वारा उपलब्ध कराया गया। ताजा भोजन पाकर जरूरतमंदो में खुशी से चेहरे खिल उठे। दोनो जगहों पर कुल 406 जरूरतमंदो ने अपनी भूख मिटाई।

राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ के मार्गदर्शक निजाम खान बताया कि जन सहयोग के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की जा रही है।जिससे शुद्ध और पौष्टिक भोजन के अभाव में भूखे जरूरतमंदों को इधर - उधर भटकना ना पड़े। सप्ताह के प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक दिवस राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ के तत्त्वाधान में निःस्वार्थ सेवाभाव से निःशुल्क भोजन वितरण कार्य का सिलसिला वर्षो से लगातार जारी है। इसी क्रम में देर शाम गुरुवार को सुल्तानपुर मेडिकल कालेज में खुशियों की थाली मुफ्त गरम ताजा खाना बाटने का कार्यक्रम सगठन के अध्यक्ष मेराज अहमद खान के संयोजन में लायंस क्लब के सस्थापक अध्यक्ष ,जिला सुरक्षा सगठन के संयोजक विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जिले के समाजसेवी सरदार बलदेव सिंह' ने मुफ्त भोजन की थाली जरूरतमंदों को देकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ द्वारा भूखे जरूरतमंदों के लिए फ्री भोजन उपलब्ध कराना सबसे महान और पुनीत कार्य है। भोजन की गुणवत्ता वास्तव में बहुत अच्छी है। दाल सब्जी ,रोटी और चावल अच्छी किस्म का है। वर्षो से भोजन बाटने का कार्य चल रहा है जिससे मरीज और तीमारदारों के अलावा भी शहर के अन्य जरूरत मंद जिनको यह पता है कि बृहस्पतिवार को निःशुल्क भोजन मिलता है वे भी भरपूर और भरपेट भोजन का लाभ ले रहे है।सगठन के समस्त टीम धन्यवाद के पात्र है और मेरी तरफ से सभी को बहुत- बहुत शुभकामनाए। ईश्वर से कामना है कि सगठन के सभी कार्यकर्ता ऐसे ही श्रद्धा और निष्ठा से नित भोजन वितरण का कार्य संचालित करते रहे।आज मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला मैं अभिभूत हूं।समाज के अच्छे लोगो से ही भारत देश में सद्भाव और समरसता की भावना कायम है।

हॉस्पिटल में भर्ती कराकर इस्टीमेट मंगाइए, इलाज का खर्च सरकार देगी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

» जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी ने सुनीं 300 लोगों की समस्याएं

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों को आश्वस्त किया कि जिन जरूरतमंद लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। इसके लिए अस्पताल से इलाज खर्च का इस्टीमेट बनाकर उनके कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। विवेकाधीन कोष से भरपूर मदद की जाएगी।

शारदीय नवरात्र के पहले दिन, गुरुवार दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात की। एक-एक करके उनकी समस्याएं सुनीं और निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उनके प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को दिए। सभी लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा।

हर बार की भांति शुक्रवार सुबह के जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता संबंधी प्रार्थना पत्र लेकर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबको मदद का भरोसा दिया। इस दौरान एक महिला की समस्या जानते ही उन्होंने अफसरों से कहा कि उक्त महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर इलाज का इस्टीमेट मंगाइए। पैसा सरकार देगी। सीएम ने लोगों से आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा और अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें ताकि इलाज के लिए किसी को परेशान न होना पड़े।

जनता दर्शन में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हर पीड़ति के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगई कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हर पीड़ति की समस्या का निस्तारण निष्पक्ष रूप से उसकी संतुष्टि के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए।

बच्चों से मिले सीएम, खूब पढ़ने को किया प्रेरित

शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों के साथ मंदिर आए बच्चों को प्यार, दुलार और आशीर्वाद दिया। बच्चों को अपने पास बुलाकर उनसे बातचीत की। उनसे नाम पूछने के साथ पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और खूब पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बच्चों को सीएम ने चॉकलेट गिफ्ट कर विदा किया।

गोशाला में जाकर की गोसेवा

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान पारंपरिक दिनचर्या में शुक्रवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गोशाला में पहुंचे। यहां उन्होंने गोसेवा में कुछ व्यतीत किया। सीएम योगी ने गोवंश को अपने हाथों से गुड़ खिलाया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 .25 करोड़ किसानों को 4,985 .49 करोड़ रुपये की 18वीं किश्त का भुगतान : कृषि मंत्री

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली 18वीं किश्त की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 05 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वेगॉल (वाशिम) में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 2,25,91,884 किसानों को कुल 4,985.49 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही 23.36 लाख लंबित किश्तों के 46.70 करोड़ रुपये का भुगतान भी किसानों के डेटा सुधार के बाद किया जाएगा।

मंत्री शाही ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से दिसंबर 2018 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाती है। इस योजना के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर चार माह में 2,000 रुपये की किश्त उनके खातों में सीधे स्थानांतरित की जाती है। शाही ने जानकारी दी कि योजना के आरंभ से जुलाई 2024 तक उत्तर प्रदेश में 17 किश्तों के माध्यम से कुल 74,492.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिससे प्रदेश के 2.76 करोड़ किसानों को कम से कम एक बार योजना का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि 17वीं किश्त का वितरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 जून 2024 को वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में किया था, जिसमें 2,14,55,237 किसानों को 4,831.10 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

शह और मात पर मुख्यमंत्री ने लिटिल चैम्प से खूब की बात

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। खेल और खिलाड़ियों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगाव जग जाहिर है। और, जब बात खेल की नन्ही प्रतिभाओं की हो तो फिर कहना ही क्या। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री में देश के सबसे कम उम्र के फीडे (विश्व शतरंज महासंघ) रेटेड खिलाड़ी, गोरखपुर निवासी कुशाग्र अग्रवाल के साथ शतरंज खेल कर उत्साहवर्धन किया। सीएम योगी ने इस लिटिल चैम्प से शतरंज के खेल में मोहरों की चाल और शह-मात पर खूब बात की।

कुशाग्र अग्रवाल, शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। कुशाग्र अभी सिर्फ 5 साल 11 माह के हैं और यूकेजी में पढ़ते हैं। पर, उनकी उपलब्धि उम्र से काफी बड़ी है। 1428 रैपिड फीडे रेटिंग हासिल कर वह इस समय भारत में सबसे कम उम्र के फीडे-रेटेड खिलाड़ी हैं। उन्होंने 4 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया और अपनी प्रतिभा के दम पर एक साल में ही फीडे रेटिंग हासिल कर ली। शतरंज का शुरुआती प्रशिक्षण उन्हें अपनी बहन अविका से मिला जो खुद भी शतरंज की बेहतरीन खिलाड़ी हैं। कुशाग्र अब तक पटना, बेंगलुरु, पुणे में आयोजित लगभग अंतरराष्ट्रीय फीडे रेटेड प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर पुरस्कार जीत चुके हैं।

गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल कुशाग्र को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया बल्कि उनके साथ शतरंज खेलकर खूब उत्साह भी बढ़ाया। उन्होंने कुशाग्र से शतरंज की चालों से जुड़ी बारीकियों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि कुशाग्र अग्रवाल की प्रतिभा को और निखारने के लिए यूपी सरकार हर तरह की मदद करेगी। उन्होंने विश्वासएम जताया कि शतरंज का नन्हा अंतरराष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी आने वाले समय में गोरखपुर और प्रदेश का नाम देश-दुनिया में रोशन करेगा।

पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए द्वितीय चरण का कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

लखनऊ। योगी सरकार द्वारा प्रदेश के पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत श्ओश लेवल और ट्रिपल सीश कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे पिछड़े वर्ग के युवाओं को डिजिटल युग में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि सरकार का यह प्रयास है कि पिछड़े वर्ग के युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य बनाया जाए। कम्प्यूटर प्रशिक्षण से यह युवक-युवतियां अपनी क्षमता को निखार सकेंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर होकर समाज में आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

नगर विकास मंत्री ए .के . शर्मा ने वाराणसी की सफाई, सीवर, जल निकासी, जलापूर्ति, मार्गप्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने वाराणसी की सफाई व्यवस्था, सीवर, जल निकासी, जलापूर्ति, मार्ग प्रकाश आदि व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के सख़्त निर्देश निकाय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों का समय है नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, छठपूजा के दौरान बनारस में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है, इस दृष्टि से युद्धस्तर पर लगकर बनारस शहर की व्यवस्थापन को सुदृढ़ करें। गंगा व अन्य नदी घाटों की सफाई सुनिश्चित कराए। मार्ग प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखें। सड़कों गलियों में कहीं पर भी अंधेरा न हो। सड़कों को अति शीघ्र गड्ढा मुक्त करें। सफाई कार्यों में लापरवाही और शिथिलता न हो, डोर टू डोर कूड़ा उठान और कूड़े के प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए। वार्ड वार और जोनवार इसकी मॉनिटरिंग की जाए। कहीं पर भी नाले नालियां चोक न हो, जिससे जलभराव हो। प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर भी कार्रवाई की जाए।

नगर विकास मंत्री शुक्रवार को जल निगम के फील्ड हॉस्टल 'संगम' में वाराणसी के सफाई कार्यों, मार्ग प्रकाश, जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था आदि कार्यों कि अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बनारस जैसे विश्व प्रसिद्ध शहर की साफ सफाई और सुंदरीकरण के कार्यों व अन्य नागरिक सुविधाओं के व्यवस्थापन में ढिलाई न बरती जाए। गंदगी कहीं पर भी न दिखे। वाराणसी नगर निगम के नवसृजित क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों में गति लाई जाए। सफाई कार्यों में मनुष्य और मशीन का सही से प्रयोग किया जाए, जो भी मशीन ख़राब हो, उसको रिपेयर कराकर उपयोग में लाया जाए। उपकरणों व मशीनों की और जरूरत हो तो उसकी भी व्यवस्था करें। लेकिन बनारस में गंदगी से समझौता नहीं किया जाएगा।

नगर विकास मंत्री ने बनारस में व्यापक स्तर पर स्ट्रीट लाइट के खराब होने, न जलने तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त न होने पर नगर आयुक्त वाराणसी अक्षत वर्मा को निर्देशित किया की नवरात्रि पर्व के दौरान ही बनारस शहर की संपूर्ण स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करा ली जाए, कहीं पर भी अंधेरा न हो, मार्ग प्रकाश व्यवस्था अच्छी हो। बनारस में कुल 62 हजार स्ट्रीट लाइट में से एक चैथाई अर्थात 7100 लाइट खराब है। इसमें से ईएसएसईएल कम्पनी द्वारा लगाई गई 38,862 लाइटों में से 4400 लाइट खराब है। यह बेहद चिंताजनक स्थित है। उन्होंने वार्डवार सभी स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, जिससे कहीं पर भी अंधेरा न रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग या एजेंसी द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाई गई हो स्ट्रीट लाइट के रखरखाव की जिम्मेदारी अंततः नगर विकास विभाग की ही होती है, जो भी कंपनी या विभाग नगर विकास विभाग से अनुमति लिए बगैर निर्माण कार्य कराए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ए0के0 शर्मा ने कहा कि ईएसएसईएल कम्पनी के कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग की जाए। जो भी वास्तविक स्थिति हो, रविवार तक निदेशक नगरीय निकाय और कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर लिया जाए और जो भी समस्यायें आ रही हों, उसका तत्काल समाधान करायें तथा ज्यादा कार्मिक लगाकर स्ट्रीट लाइट का कार्य सही से करायें। स्ट्रीट लाइट को दिन में बंद करने के लिए जहां पर भी फेज्ड वायर न लगा हो, ऐसे स्थानों पर फेज्ड वायर लगाया जाए। ऊर्जा मंत्री ने मुख्य अभियंता वाराणसी अरविन्द कुमार सिंघल को निर्देशित किया कि जहां कहीं पर भी एबी केबल के कारण स्ट्रीट लाइट के जलने में व्यवधान हो रहा है।

योगी सरकार ने 80 प्रतिशत खरीफ की फसल का सर्वे किया पूरा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश भर में बोई जाने वाली खरीफ (2024-25) की फसल के डिजिटल क्रॉप सर्वे का 80 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है। प्रदेश के 84 हजार से अधिक राजस्व गांवों में शुरू किये गये डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत 47 हजार से अधिक गांवों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है जबकि कुल साढ़े चार करोड़ से अधिक प्लॉट्स (गाटा संख्या) में बोई खरीफ की फसल के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। यह कुल (साढ़े पांच करोड़ से अधिक) प्लॉट्स का 80 प्रतिशत है। इन कंप्लीट सर्वे में से 3 करोड़ से अधिक प्लॉट्स के सर्वे को अप्रूवल भी मिल चुका है, जो 82 प्रतिशत है। वहीं सर्वे में प्रदेश के टॉप टेन जिलों में जौनपुर अव्वल रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर गाजियाबाद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की आय बढ़ाने एवं उनके खुशहाल जीवन के लिए फसलों के डिजिटल क्राप सर्वे का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश के 75 जिलों के 91,609 राजस्व गांव के 5,81,23,573 प्लॉट्स (गाटा संख्या) का डिजिटल मैप उपलब्ध कराया गया। ऐसे में योगी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को विजन के रूप में आगे बढ़ा रही है। इसके तहत योगी सरकार ने प्रदेश भर में खरीफ की फसल के डिजिटल क्रॉप सर्वे के निर्देश दिये। उन्होंने यह सर्वे 23 अगस्त से 5 अक्टूबर तक पूरे करने के निर्देश दिये थे। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के 84,159 गांवों में सर्वे का काम शुरू किया गया। इसके सापेक्ष 2 अक्टूबर तक 47,098 राजस्व गांवों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जो 52 प्रतिशत है। वहीं शेष राजस्व गांवों में सर्वे का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान 2 अक्टूबर तक 4,63,22,564 प्लॉट्स (गाटा संख्या) के सर्वे के काम को पूरा कर लिया गया है, जो 80 प्रतिशत है जबकि 3,76,22,171 प्लॉट्स (गाटा संख्या) के सर्वे को अप्रूव्ड किया जा चुका है। यह कुल प्लॉट्स का 82 प्रतिशत है। वहीं शेष 1,18,01,009 प्लॉट्स (गाटा संख्या) के सर्वे के अप्रूवल का काम युद्धस्तर पर चल रहा है।

जौनपुर पहले तो गाजियाबाद दूसरे स्थान पर

खरीफ की फसल के डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत प्रदेश के टॉप टेन जिलों में जौनपुर ने पहला स्थान हासिल कर बाजी मारी है। जौनपुर को 17,33,553 प्लॉट्स (गाटा संख्या) के सर्वे का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 15,69,912 प्लॉट्स का सर्वे पूरा कर लिया गया है। वहीं सर्वे के सापेक्ष 15,61,266 प्लॉट्स के सर्वे को अप्रूव्ड भी किया जा चुका है, जो कुल प्लॉट्स का 99.45 प्रतिशत है। इसी तरह गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है। गाजियाबाद को 1,45,688 प्लॉट्स (गाटा संख्या) के सर्वे का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 1,33,735 प्लॉट्स का सर्वे पूरा कर लिया गया है। वहीं सर्वे के सापेक्ष 1,31,581 सर्वे को अप्रूव्ड भी किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 98.39 प्रतिशत है। वहीं अमरोहा तीसरे स्थान पर है। अमरोहा को 4,84,061 प्लॉट्स (गाटा संख्या) के सर्वे का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 4,01,698 प्लॉट्स का सर्वे पूरा कर लिया गया है। वहीं सर्वे के सापेक्ष 3,92,771 प्लॉट्स के सर्वे को अप्रूव्ड किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 97.78 प्रतिशत है। इसके अलावा बस्ती चौथे स्थान पर है। बस्ती को 13,30,380 प्लॉट्स (गाटा संख्या) के सर्वे का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 11,31,704 प्लॉट्स का सर्वे पूरा कर लिया गया है। वहीं सर्वे के सापेक्ष 11,05,397 सर्वे को अप्रूव्ड भी किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 97.68 प्रतिशत है। आजमगढ़ पांचवे स्थान पर है। आजमगढ़ को 14,24,270 प्लॉट्स (गाटा संख्या) के सर्वे का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 13,58,149 प्लॉट्स का सर्वे पूरा कर लिया गया है। वहीं सर्वे के सापेक्ष 13,17,780 सर्वे को अप्रूव्ड भी किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 97.03 प्रतिशत है। इसके अलावा हमीरपुर छठे, मैनपुरी सातवें, महोबा आठवें, गाजीपुर नौवें और शामली दसवें स्थान पर है।

रेशन उद्योग में नवाचार, उत्पादन और डिजाइनिंग को प्रोत्साहन देने के लिए 8 श्रेणियों में पुरस्कार देगी योगी सरकार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार के रेशम विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में रेशम उत्पादन और संबंधित क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को पं. दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान 08 विभिन्न श्रेणियों में दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य रेशम उद्योग में नवाचार, उत्पादन और डिजाइनिंग को प्रोत्साहन देना है।

रेशम क्षेत्र में उत्कृष्टता की पहचान करने और इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिन्होंने कोकून उत्पादन, रेशम फिनिश्ड प्रोडक्ट में नवाचार, सर्वोच्च कोयाधागा विक्रय, सर्वोच्च फिनिश्ड प्रोडक्ट विक्रय, रेशम निर्मित परिधान एवं अन्य उत्पाद में सर्वोत्तम डिजाइनिंग और लाइफटाइम एचीवमेंट जैसी श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि रेशम उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस सम्मान का उद्देश्य प्रदेश के उन कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है जो रेशम उद्योग में निरंतर सुधार और नवाचार कर रहे हैं। रेशम मंत्री राकेश सचान ने प्रदेश के सभी कारीगरों, उद्यमियों और रेशम उत्पादकों से इस सम्मान के लिए आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार न केवल उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि इससे जुड़े लोगों को उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा का उचित सम्मान भी मिलेगा। हर श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के रूप में 50,000 रूपए की नकद राशि और द्वितीय पुरस्कार के रूप में 25,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। साथ ही विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान न केवल वित्तीय सहायता का माध्यम बनेगा, बल्कि यह उत्कृष्टता की पहचान के रूप में भी कार्य करेगा। कार्यक्रम में रेशम उद्योग से संबंधित रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन भी किया जाएगा। इसके साथ ही, रेशम मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा, जो रेशम उत्पादन और व्यापार से जुड़े व्यक्तियों के लिए ज्ञान और संसाधनों का एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से रेशम उद्योग के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी नवीनतम जानकारियां और अपडेट्स उपलब्ध होंगे। सम्मान के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, 2024 निर्धारित की गई है। इच्छुक प्रतिभागी अपने आवेदन पत्र रेशम निदेशालय, विश्वास खंड-3, गोमतीनगर, लखनऊ को भेज सकते हैं। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट और रेशम मित्र पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

और सशक्त होंगी बेटियां, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति बढ़ेगी जागरूकता

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार अपने विजन को प्रदेश में 'मिशन शक्ति' के रूप में आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मिशन को और अधिक प्रभावी बनाने और महिलाओं को और अधिक सशक्त करने के लिए शारदीय नवरात्रि में इसके पांचवें चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। मिशन शक्ति के पांचवें चरण के तहत व्यापक पैमाने पर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है जो कि दिसंबर माह तक चलेगा। इन कार्यक्रमों में महिलाओं के साथ-साथ बच्चों को भी सम्मिलित किया गया है। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑपरेशन मुक्ति, बाल कार्निवाल, वीरांगना दिवस, स्वावलंबन कैंप समेत कई कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के प्रति जागरूकता लाने के साथ-साथ उन्हें इससे लाभान्वित करना भी है।

11 अक्टूबर तक चलाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आगामी मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत अक्तूबर से दिसंबर तक जो गतिविधियां संचालित की जानी हैं, उसके अनुसार 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लैंगिक समानता पर सेमिनार के साथ ही सफल महिलाओं के साथ टॉक शो, एक दिन की सांकेतिक जिलाधिकारी, कन्या जन्मोत्सव, बाल विवाह, संवाद, घरेलू हिंसा व कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न, अनंता जैसे विषयों पर जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। 11 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन होगा, जिसमें प्रत्येक आंगनबाड़ी तथा राजकीय बालिका/शिशु गृहों में विशेष कन्या पूजन व उनके लिए प्रसाद ग्रहण का आयोजन किया जाएगा।

बाल विवाह और बाल श्रम के विरुद्ध चलेगा 'ऑपरेशन मुक्ति'

इसी माह 21 से 31 अक्तूबर तक ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत बाल विवाह तथा बाल श्रम के विरुद्ध सप्ताह भर जागरूकता एवं रेस्क्यू के लिए वृहद अभियान चलेगा। इस दौरान विभागों एवं प्राधिकारियों के बीच समन्वय के साथ कार्य करते हुए बाल विवाह या बाल श्रम के प्रकरणों में बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन को संचालित किया जाएगा। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना से जोड़ा जाएगा।

'बाल कार्निवाल' में बच्चों के हुनर को मिलेगी पहचान

10 से 14 नवंबर के बीच बाल कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। इसमें योग व मेडिटेशन के अतिरिक्त बच्चों द्वारा महापुरुषों के जीवन पर आधारित नाटक एवं ड्रामा का प्रदर्शन होगा। साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जबकि नृत्य गायन प्रतियोगिताओं के साथ-साथ पेंटिंग प्रतियोगिता कराई जाएगी। 14 नवंबर को बाल दिवस के उपलक्ष्य में कार्निवाल समापन समारोह में बच्चों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे म्यूजिक, गीत, गान, नाटक आदि का आयोजन, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत बच्चों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रतियोगितों में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

वीरांगनाओं को समर्पित होगा 'वीरांगना दिवस'

19 नवंबर से प्रदेश के समस्त जनपदों में भव्य समारोह का आयोजन करते हुए वीरांगना दिवस पर समाज में बदलाव के लिए प्रयासरत महिलाओं की प्रेरक कहानियों को जनपद स्तर पर विभिन्न माध्यमों से जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान ऐसी वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिससे ये महिलाएं समाज में अन्य बालिकाओं तथा महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन सकें। साथ ही प्रदेश में संचालित सभी बाल देखरेख संस्थाओं, महिला आश्रय गृहों में भी झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर नुक्कड़ नाटक या स्टोरी टेलिंग सत्र का आयोजन कराया जाएगा। इसके अलावा 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस पर संस्थाओं में बाल अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तर पर कौशल विकास में शामिल बच्चों पर आधारित हैंडबुक, कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया जाएगा।

महिला स्वावलंबन के लिए चलेगा 'स्वावलंबन कैंप'

30 नवंबर से स्वावलंबन कैंप की शुरुआत होगी। इसमें केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं (मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, निराश्रित महिला पेंशन, स्पॉन्सरशिप योजना) से लाभान्वित किए जा सकने वाले परिवारों, महिलाओं तथा बच्चों के आवेदनों की समस्त कार्यवाही इन वन विंडो कैंपस के माध्यम से पूरी की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के संबंध में संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार व महिलाओं एवं बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों व प्रावधानों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा। इसी तरह, 4 दिसंबर को समस्त जनपदों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित स्थानीय व आंतरिक परिवाद समितियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा।

हक की बात जिलाधिकारी के साथ

6 दिसंबर को जनपद स्तर पर यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थर पर लैंगिक उत्पीड़न तथा दहेजा हिंसा आदि की पीड़ित महिलाओं के संरक्षण, सुरक्षा तंत्र, सुझावों तथा सहायता के लिए जिलाधिकारी के साथ 2 घंटे के पारस्परिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा, 10 दिसंबर को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल सभाओं का आयोजन तथा महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं 16 दिसंबर को प्रदेश के समस्त वन स्टॉप केंद्रों पर जन प्रतिनिधियों के साथ विभागीय योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। यही नहीं, प्रदेश में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पीड़ित बच्चों मुख्य रूप से बालिकाओं को कानूनी प्रक्रिया के दौरान समर्थन देने के लिए लगभग 300 सहायक व्यक्तियों का आवासीय प्रशिक्षण भी कराया जाएगा।

आकस्मिक सहायता के लिए संचालित सेवाओं के प्रति किया जाएगा जागरूक

कार्ययोजना के सुगम संचालन के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके तहत मिशन के दौरान महिलाओं तथा बच्चों को आकस्मिक सहायता प्रदान करने के लिए संचालित 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1090 विमन पावरलाइन, 112 पुलिस सहायता व महिलाओं तथा बालिकाओं को एक ही छत के नीचे रेस्क्यू, आश्रय, विधिक/पुलिस परामर्श तथा चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर तथा अन्य योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया है कि

उत्तर प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था और जातिवाद की जहरीली होती राजनीति

लोकसभा चुनावों में पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़कर 37 हो जाने से समाजवादी पार्टी विशेष उत्साह में है और जहाँ जहाँ भी उसके सांसद जीते हैं वहाँ वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता न केवल अराजकता का वातावरण बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं वरन जातिवादी जहर घोलने का प्रयास भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश की योगी सरकार लगातार अपराध और अपराध जगत पर जीरो टालरेंस की नीति पर चल रही है जिसमें कुख्यात माफियाओं व अपराधियो के एनकाउंटर हो रहे हैं तथा बुलडोज़र भी चलाये जा रहे हैं, कई जगह अपराधी स्वयं ही आत्समर्पण भी कर रहे हैं या फिर अपना काम धंधा बदल रहे हैं। प्रदेश का जन सामान्य योगी सरकार की बुलडोज़र नीति से प्रसन्न है जबकि विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा था कि बुलडोज़र से लोगों को डराया जा रहा है या अल्पसंख्यको को सताया जा रहा है आदि-आदि। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर अंतरिम रोक लगाई तो पूरा विपक्ष खुशियाँ मनाने लगा जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को अपने आदेश से अलग रखा था। योगी राज्य में बुलडोज़र केवल अतिक्रमण पर ही चलता है अतः प्रशासन को अपना काम करने में कोई समस्या नहीं आई।

आश्चर्यजनक रूप से समाजवादी नेता अपनी जातिवाद की राजनीति को और पैना करने के लिए अपराधियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। वहीं विगत दिनों हुई कुछ आपराधिक घटनाओं में शामिल लोग समाजवादी पार्टी से सम्बंधित रहे हैं संभवतः यही कारण है कि समाजवादी नेता अखिलेश यादव सहित अन्य सभी जातिवादी नेता जातिवाद के जहर को और तीखा कर रहे हैं। अयोध्या से लेकर कनौज तक दुष्कर्म की जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं उसमें सपा कनेक्शन मिला, प्रयागराज में अवैध मदरसे में चल रहा जाली नोट का व्यापार व फिर कौशाम्बी में जाली नोट खपाने वाले सपा के दो नेता अपने दस सहयोगियों के साथ पकड़े गए स्वाभाविक रूप से आपराधिक घटनाओं में लिप्त पार्टी को बैकफुट पर जाने से बचाने के लिए ही अपराध की वीभत्सता तथा गम्भिरता की जगह अपराधी की जाति बीच में लाई जा रही है। अगस्त माह के अंत में सुल्तानपुर में डकैती डालने आये गिरोह के सदस्यों का एनकाउंटर हुआ जिसमें से एक मंगेश यादव के नाम पर समाजवादी नेता यादव समाज की सहानुभूति बटोरने के लिए उसके घर पहुंच गये और उसका महिमा मंडन करते हुए कहा कि यह एनकाउंटर नहीं एक हत्या है और अब सपा इस मामले को आगामी विधानसभा सत्र में भी जोर शोर से उठाने जा रही है। समाजवादी नेता आजकल जातिगत आधार पर ही अपराध और अपराधियों का संरक्षण व महिमामंडन कर रहे हैं।

प्रदेश की राजनीति में आज सभी दल अपराधी की जाति देखकर उस पर होने वाली कार्यवाही का तीखा विरोध कर रहे हैं जबकि प्रदेश में 2012 से 2017 तक सपा सरकार के शासन काल में पुलिस मुठभेड़ में 34 अपराधी मारे गये थे तथापि उनके शासनकाल में अपराध और अपराधियों का जोरदार बोलबाला था। एक समय था कि कोई सपने में भी नहीं सोच पाता था कि प्रदेश को कभी अतीक जैसे माफियाओं से मुक्ति मिलेगी या फिर बड़े सफेदपोश लोग जेल जाएंगे।

पिछली सरकारों के कई एनकाउंटर में तो मजिस्ट्रेट जांच तक नहीं ती थी। जबकि योगी सरकार में सभी एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच हो रही है यहां तक कि कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में हुई स्वाभाविक मौत की भी जांच हुई।

योगीराज में प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने लिए साढ़े सात वर्षों में 49 कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त 872 नशा व हथियार तस्करी अपराधी और 379 साइबर अपराधियां को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3,970 संगठित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश सरकार अवैध नशे के खिलाफ भी व्यापक अभियान चला रही हे जिसमें अभियुक्तों से सर्वाधिक गांजा बरामद हुआ है व अन्य नशीले पदार्थ भी बरामद हो रहे हैं । समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने एसटीएफ को भी नहीं छोड़ा ओर उसमें शामिल अधिकारियों की जाति को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उकेर दिया ओर बताया कि कौन सा अधिकारी किस जाति का है। जब जातिवाद की राजनीति बहुत उग्र होने लग गई तब आंकड़ों को देखने से स्पष्ट हुआ कि विगत 7 साल में 207अपराधी एनकाउटर में मारे गये जिसमें- 67 मुसिलम, 20 ब्राहमण, 18 ठाकुर, 17 जाट और गुर्जर 16 यादव, 14 दलित, तीन ट्राइबल, दो सिक्ख, 8 ओबीसी और 42 दूसरी जातियों के थे। जिस प्रकार से अपराधियों के पक्ष में जाति की राजनीति हो रही है वह सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। यह कहना पूरी तरह से गलत है कि यूपी की पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही हैं या फिर अपराधियों को पकड़ रही है। प्रदेश सरकार अपराधियों का जाति और मजहब नहीं देखती। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा हर कोई कर रहा है बड़े बड़े उद्योगपति व निवेशक प्रदेश आ रहे हैं और यही बात विपक्षी नेताओं को रास नहीं आ रही है ।

चुनावी बांड की कहानी, निर्मला सीतारमण की परेशानी

अदेश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके सह-आरोपी बनाए गए कर्नाटक के भाजपा के नेताओं तथा ईडी अधिकारियों ने बेशक राहत की सांस ली होगी

राजेंद्र शर्मा

फिर भी इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावी मुद्दों की भीड़-भाड़ में, चुनावी बांड की गड़बड़ियों का मुद्दा कहीं दब सा गया था। निर्मला सीतारमण व अन्य भाजपा नेताओं पर एफआईआर के प्रसंग ने इस मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत को देखते हुए, सत्ताधारी गुट के लिए इसे दबाना अब उतना आसान नहीं होगा। इस संदर्भ के अंतर के अलावा अब की स्थिति एक महत्वपूर्ण अंतर और है। अदेश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके सह-आरोपी बनाए गए कर्नाटक के भाजपा के नेताओं तथा ईडी अधिकारियों ने बेशक राहत की सांस ली होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ चुनावी बांड के नाम पर, अवैध हफ्ता वसूली के आरोपों की जांच पर अपने अंतरिम आदेश के जरिए फिलहाल रोक लगा दी है। आरोपियों में से एक, भाजपा नेता नलिन कुमार कतील की याचिका पर, अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट के एकल पीठ ने उन्हें उक्त राहत दी है। याचिका में उस प्राथमिकी को ही चुनौती दी गयी है, जिसमें कतील व अन्य को नामजद किया गया है। याद रहे कि एक गैर-सरकारी संगठन की याचिका पर, एक विशेष अदालत के आदेश पर ही, निर्मला सीतारमण व अन्य के खिलाफ चुनावी बांड के नाम पर अवैध वसूली के आरोपों में कर्नाटक में एफआईआर दर्ज की गयी थी। स्वाभाविक है अगले कदम के रूप में आरोपों के संबंध में जांच शुरू होनी चाहिए थी, जिसे फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश ने कम से कम अगली सुनवाई तक के लिए रोक दिया है।

बहरहाल, इस तात्कालिक राहत से सुश्री सीतारमण और उनसे बढ़कर उनकी पार्टी के नेतृत्व के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आएगी, यह मानना मुश्किल है। इसकी वजहें दो हैं। पहली तो यह कि यह राहत फौरी यानी अस्थायी राहत ही है। अदालत से इस तरह की अस्थायी राहत मिलना तो आसान है, लेकिन एक अदालती आदेश के फलस्वरूप दर्ज की गयी एफआईआर को ही निरस्त करने का अदालती फैसला हासिल करना, लगभग नामुकिन है। यानी आरोपों पर जांच का वास्तव में आगे बढ़ना नहीं बढ़ना अपनी जगह, लेकिन इतना तय है कि यह प्रसंग आसानी से ठंडा पड़ने वाला नहीं है और यहीं से भाजपा की परेशानी की दूसरी वजह शुरू होती है। इसका संबंध इस तथ्य से है कि इस पूरे प्रसंग ने, सत्ता के बल पर किए गए एक बड़े घोटाले के रूप में, चुनावी बांड के मुद्दे को फिर से नया कर दिया है। कहने की जरूरत नहीं है कि सत्ताधारी भाजपा और उसके संघ परिवार ने कितनी मेहनत कर के और कितने संसाधनों को झोंककर, चुनावी बांड के मुद्दे का धीरे-धीरे सार्वजनिक बहस से गायब ही हो जाना सुनिश्चित किया था। जाहिर है कि इसमें सत्ताधारी दल की सबसे ज्यादा मदद तो सर्वोच्च अदालत ने ही की थी, जिसने अपने ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बांड की पूरी की पूरी व्यवस्था को असंवैधानिक तथा गैर-कानूनी करार देकर खारिज तो किया था और इसके जरिए क्विड प्रो क्वो यानी चंदा लाओ और लाभ पाओ की व्यवस्था चल रही की संभावना मानी भी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने ही फैसले से उजागर हुई आर्थिक गड़बड़ियों की आगे किसी जांच का रास्ता खोलने से इंकार कर दिया।

यह इसके बावजूद था कि स्टेट बैंक के चुनावी बांड के जरिए पैसे की यात्रा की पूरी ट्रेल जाहिर करने में असमर्थता जताने के बावजूद, चुनावी बांडों के सिलसिले में, इन बांडों की खरीद तथा राजनीतिक पार्टियों द्वारा उनके प्राप्त किए जाने की जानकारियों को उनके संदर्भ में रखकर, मीडिया में अनेक जानकार विश्लेषकों ने बड़े विस्तार से, सटीक जानकारियों व साक्ष्यों के साथ, गड़बड़ी के बेशुमार मामले उजागर किए थे। इसी क्रम में अवैध चंदा वसूली के लिए, जिसे मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने, जानी-पहचानी 'हफ्ता वसूली' का ही एक रूप बताया था, केंद्रीय एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी, आयकर आदि के दुरुपयोग के भी कितने ही मामले सामने आए थे। केंद्रीय एजेंसियों की छापों समेत विभिन्न कार्रवाइयों और चुनावी बांड के जरिए चंदे के कई अलग-अलग पैटर्नों की भी पहचान की गयी थी। जहां कुछ मामलों में केंद्रीय एजेंसियों के छापे/ कार्रवाई के फौरन बाद, संबंधित कंपनियों द्वारा सत्ताधारी भाजपा को चंदा दिया जाना शुरू कर दिया गया था, वहीं कुछ और मामलों में पहले से चंदा दे रही कंपनियों ने छापे के बाद, उल्लेखनीय रूप से ज्यादा चंदा देना शुरू कर दिया था। और कुछ और मामलों में बार-बार छापे के जरिए कंपनियों से बार-बार पैसे की वसूली की जा रही थी। बेशक, यह सब उस सामान्य या सद्भावनापूर्ण वातावरण में हो रहे लेन-देन के ऊपर से था, जिसे 'चंदा दो और धंधा लो' कहा जा सकता है। यानी सरकारी ठेके आदि के रूप में सरकार से उपकार लो और बदले में बांड के जरिए चंदा देकर अपना कर्जा उतार दो। इन तमाम असामान्यताओं के बरक्स इस चुनावी बांड भंडाफोड़ में ऐसी कंपनियों के सत्ताधारी पार्टी को बड़े पैमाने पर चंदा देने के मामले भी सामने आए, जिनके चंदे का किसी भी तरह से धंधे के हिस्से के तौर पर कोई तर्क ही नहीं बनता था। मिसाल के तौर पर कई मामलों में कंपनियों ने अपने कुल मुनाफे से कई-कई गुना ज्यादा चंदा चुनावी बांड के जरिए दिया था, तो कुछ मामलों में तो इन कंपनियों की कुल कीमत से भी कई-कई गुना चंदा दिया गया था, जो साफ तौर पर इन कंपनियों के खोखा कंपनियों की तरह काम कर रहे होने का यानी मनी लॉन्डरिंग का ही मामला नजर आता था। वास्तव में जब इस चुनावी बांड योजना के सिलसिले में, पहले से चले आते राजनीतिक चंदा कानून के इस प्रावधान को संशोधित किया जा रहा था कि कोई भी कंपनी, अपने पिछले तीन साल के मुनाफे का ज्यादा से ज्यादा 7 फीसद ही राजनीतिक चंदे के तौर पर दे सकती थी, और इस पूरी की पूरी पाबंदी को ही हटाया जा रहा था, तभी विभिन्न हलकों ने इसकी आशंका जताई थी कि यह चुनावी चंदे के नाम पर मनी लॉन्डरिंग का रास्ता खोल सकता था। दुर्भाग्य से इस मामले में बदतरीन आंशकाएं सच साबित हुई थीं। इसके बावजूद, मोदी सरकार से और उसकी एजेंसियों से तो इन गड़बड़ियों की जांच और दोषियों को सजा दिलाने की उम्मीद की नहीं जा सकती थी। आखिरकार, इन गड़बड़ियों की सबसे बड़ी लाभार्थी तो सत्ताधारी पार्टी ही थी। इन उजागर हो गयीं गड़बड़ियों तक की किसी भी तरह की जांच कराना तो दूर रहा, वर्तमान निजाम ने तो चुनावी बांड की व्यवस्था का बचाव करने की ही कोशिश की थी। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस व्यवस्था को अवैध तथा असंवैधानिक बताकर, पूरी तरह से रद्द कर दिए जाने के बावजूद, आम चुनाव के दौरान खुद प्रधानमंत्री मोदी भी, न सिर्फ इसे 'नेक नीयत से लाई गयी योजना' बताकर इसका बचाव कर रहे थे बल्कि इसके आलोचकों को भी यह कहकर चुनौती दे रहे थे कि आज जो विरोध कर रहे हैं, बाद में पछताएंगे! बेशक, सत्ताधारी पार्टी के पर्दापोशी के इन सारे प्रयासों से और चुनावी बांड के मुद्दे को ही दबाने की उसकी कोशिशों से, यह मुद्दा कोई पूरी तरह से दब नहीं गया था। वास्तव में चुनावी बांड से जुड़े घोटालों की प्रतिध्वनि भी एक वजह थी कि आम चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपने तमाम छाती पीटने और विपक्ष को भ्रष्ट साबित करने की अपनी सारी कोशिशों के बावजूद, सत्ताधारी पार्टी को विपक्ष पर भ्रष्ट का लेबल चिपकाने में कोई कामयाबी नहीं मिली थी। इसीलिए तो, स्वयं मोदी से लगाकर नीचे तक, सत्ताधारी गुट के सारे मुखों को, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अपने आजमाए हुए नुस्खे को ही आजमाना पड़ा था और समर्थक हिंदुओं को यह समझाना पड़ा था कि विपक्षी अगर सत्ता में आ गए तो, उनके मंगल सूत्र से लेकर आरक्षण तक, सब कुछ छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। और इसके बावजूद, जनता ने सत्ताधारी पार्टी को बहुमत से काफी नीचे, 240 की गिनती पर ही रोक दिया।

संपादक की कलम से

जहां 'कंक्रीट का जंगल' बढ़ रहा है, वहीं 'हरियाली की चादर' सिमट रही है

प्रभात पांडेय

ब्राजील में अमेज़न नदी की दो सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक सोलिमोस का जलस्तर सोमवार को अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जो अमेज़न क्षेत्र में अब तक का सबसे खराब सूखा है, जिससे नदी के किनारे बसे गांवों में भोजन, पानी और परिवहन के बिना फंसे रहने की स्थिति पैदा हो गई है।

ब्राजील के ताजा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, अमेजन वर्षावन जिसे प्रायः 'पृथ्वी के फेफड़े' कहा जाता है वर्तमान में एक अप्रत्याशित और गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं। अल नीनो और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न यह पर्यावरणीय संकट पांच देशों के निवासियों के जीवन में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, जिससे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है।अमेजन नदी में दुनिया के कुल ताजे पानी का 20 प्रतिशत मौजूद है, लेकिन इस समय इस क्षेत्र के अधिकांश घरों के नलों में पानी नहीं है। कई देशों में अमेजन नदी की कई सहायक नदियां सूखे का शिकार हो गई हैं। अमेजन के के मुख्य प्रवाह में जल स्तर प्रतिदिन लगभग 13 से 14 सेमी गिर रहा है जो सामान्य से काफी नीचे माना जाता है। नदियों और झरनों के लुप्त होने से परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। अटलांटिक की असामान्य गर्मी ने मुख्य रूप से क्षेत्र की नदियों को सूखने में योगदान दिया है।

औद्योगिक विस्तार तथा नई आवासीय व सड़क योजनाओं आदि के कारण रेवाड़ी जिले में 'कंक्रीट का जंगल' जहां बढ़ रहा है, वहीं हरियाली की चादर सिमट रही है। पर्यावरण संरक्षण का अब तक का सच कुछ ऐसा ही है। इन प्राकृतिक विपदाओं के लिए हम प्रकृति पर चाहे जितना भी दोष मढ़ लें मगर सच्चाई यह है कि हम प्रकृति के साथ जीना सीखने के बजाय प्रकृति को अपनी सहुलियत से अपनी मर्जी के हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हालाकि, पिछले कुछ समय से पर्यावरण को लेकर सरकार व प्रबुद्ध समाज में चिंता बढ़ी है और प्रयास भी शुरू हुए है, लेकिन अभी तक किए गए प्रयास फलीभूत नहीं हुए है।

देश-दुनिया में जिस तरह से जंगलों को खत्म किया जा रहा है, पॉलीथिन की खुलेआम बिक्री हो रही है, पेड़ों पर कुल्हाड़ी चल रही है, जल-जंगल व जमीन के संरक्षण की योजनाओं में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उससे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ढर्रा बदले बिना पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य हासिल कर पाना संभव नहीं होगा। वन विभाग बेशक हर वर्ष लाखों पौधे लगाता है, लेकिन पिछले 10 वर्ष में लगाए गए पौधों की ही गिनती की जाए तो हिसाब-किताब देना मुश्किल हो जाएगा। अधिकाश पौधे जहा पेड़ बनने से पूर्व ही दम तोड़ देते है, वहीं पेड़ बनने पर बेरहमी से कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें परिपक्व होने से पहले ही खात्मा भी कर दिया जाता है।

आबादी बढ़ने के साथ घर-मकान की जरूरत हुई तो लोगों ने जंगल काट कर मकान बना लिए। खेतिहर भूमि पर प्लाटिंग हो गई और भवन खड़े हो गए। हरियाली खो गई तो अब छाया के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। समय रहने इस ओर नहीं चेते तो दिक्कतें लाजिमी है। तेजी से हो रहे नगरीयकरण का असर है कि आबादी बढ़ने से लोग पक्के बहुमंजिला भवन बना रहे हैं। कंक्रीट के ये जंगल हरियाली को खत्म कर ही खड़े किए जा रहे हैं। देखने में आया है कि जिन स्थानों पर दस वर्ष पूर्व घनी हरियाली और छाया थी वहां अब कंक्रीट के मकान बन गए हैं। जो पौधे लगाए गए हैं वह काफी छोटे हैं इस वजह से पुराने वृक्षों की तुलना में गर्मी कम करने में उतने असरदार भी नहीं हैं।

प्रकृति के विनाशी स्वरूप या चिढ़चिढ़ेपन के लिये अगर हम प्रकृति को ही दोषी मानें तो सही नहीं होगा। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है और हम प्रकृति को अपने हिसाब और सुविधा से चलाना चाहते हैं। हिमालय का पूर्वी हिस्सा जिसे उत्तर पूर्व कहा जाता है, जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया के 18 हॉट स्पॉट्स में से एक माना जाता है। लेकिन बेतहाशा मानव दबाव, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जगह बदल-बदल कर खेती (झूम खेती) तथा बेतरतीव औद्योगीकरण तथा शहरीकरण जैसी गतिविधियों के कारण वहां निरन्तर वनों का विनाश हो रहा है।

वातावरण में कार्बनडाइऑक्साइड जैसी गैसें बढ़ रही हैं और उन घातक गैसों को पीकर ऑक्सीजन छोड़ने वाले वन सिमट रहे हैं। अगर आप भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की 1995 और 2013 की वन स्थिति सर्वे रिपोर्टों का मिलान करें तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम हिमालयवासी अपने आश्रयदाता हिमालय के तंत्र को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं।

शहरी संस्कृति और सुविधाओं ने भी गाँवों की हरियाली छीनने में बड़ा योगदान दे रही हैं। ऊपर से विभिन्न कारणों/बहानों से गाँव खाली हो रहे हैं, बल्कि कहें उजाड़ हो रहे तो ग़लत न होगा। सिर्फ इतना कहने पर से कि गाँवों में हरियाली सिमटी जा रही है, से हम दोष मुक्त नहीं हो जाते। हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर अपने लिए कुआं और खाई जैसी स्थिति ला रहे। इतना ही नहीं पेड़ों को आधार मान कर होने वाली तमाम रीतियां, मान्यताएं, परंपराएं भी औपचारिकता की भेंट चढ़ती जा रही हैं। जिसके फलस्वरूप भी हरियाली का अस्तित्व खो रहा है।कोविड के दौरान हुए कटु अनुभवों के बाद भी हम आप सचेत होने के बजाय हरियाली मिटाने पर आमादा हैं।शहर तो शहर, गाँव भी हमारी, आपकी उदंडता का दंश झेलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

भारत में आज करीब 38 प्रतिशत लोग शहरों में बस चुके हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यह संख्या बढ़ती चली जाएगी। किसी भी शहर को इसके प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या के दबाव के अनुसार देखा जाता है उदाहरण के लिये आज गांवों में प्रति वर्ग किलोमीटर 125-400 की जनसंख्या है वहीं शहरों में यह संख्या 900 से लेकर 25000 के बीच में है जिनमें मुंबई व दिल्ली जैसे शहर आते हैं। कोई भी शहर क्षमता से अधिक जनसंख्या के दबाव को नहीं झेल सकता है।

प्रदूषण और पर्यावरण भी रहने लायक शहरों की सूची तैयार करने का आधार रहा है। अब आज मुंबई को देखें तो पिछले दो महीने से देश की आर्थिक राजधानी यदाकदा जलमग्न हो जा रही है। अनुचित व अनियोजित कंस्ट्रक्शन शहर में पारिस्थितिकी अनियमितताओं को जन्म देती है। उधर दिल्ली के भी हालात पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बेहतर नहीं समझे जा सकते। यहां का वायु प्रदूषण हो या फिर शीतलहर हो या फिर गर्मियों में प्रचंड तूफान हो या लू, 12 महीनों यह शहर किसी न किसी पर्यावरणीय संकट से घिरा रहता है। और इससे तमाम तरह की इंसानी दिक्कतें सामने आती हैं। बढ़ती आबादी पानी और प्राणवायु पर ज्यादा बड़े संकट खड़े करती है। यह प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटा देती है। प्रकृति का सिद्धांत है कि ज्यादा जनसंख्या वायु-पानी में असंतुलन को पैदा करती है।

पिछले कुछ दशकों में हमने प्रगति की ओर अवश्य ही बड़े-बडे कदम उठाये हैं। आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं। तमाम भौतिक उपलब्धियों के बीच प्राकृतिक संसाधनों की अनदेखी बढ़ती गई है। जिसका नतीजा सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए जल, जीवन और हरियाली को बचाए रखने के लिए हम सभी को एक होकर अपनी-अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

अजब-गजब

सुल्तान ने एक नर्तकी के लिए बनवाई थी यह अनोखी जगह, यहां से बोली हुई बात 2 किलोमीटर दूर तक देती थी सुनाई!

सुल्तान ने एक नर्तकी के लिए बनवाई थी यह अनोखी जगह, यहां से बोली हुई बात 2 किलोमीटर दूर तक देती थी सुनाई!

हैदराबाद में घूमने लायक बहुत सारी जगहें हैं। तारामती बारादरी मंडप भी इनमें से एक है। हैदराबाद के इब्राहिम बाग की पहाड़ी पर यह जगह है। 17वीं सदी में इसको बनवाया गया था। यह क्षेत्र अब हैदराबाद शहर की सीमा में आता है। पर्यटन विभाग का मानना है कि इसका नाम गोलकुंडा के सातवें सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की पसंदीदा नर्तकी तारामती के नाम पर रखा गया था।

पर्यटन विभाग के अनुसार तारामती बारादरी का नाम सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह और नर्तकी तारामती के बीच की रोमांटिक कहानी से जुड़ा है। कहा जाता है कि सुल्तान तारामती की आवाज को गोलकुंडा किले से सुनते थे। वह सेराई में यात्रियों के लिए गाती थीं। यह आवाज हवा में बहकर किले तक पहुंचती थी, जो लगभग दो किलोमीटर दूर थाह। हालांकि, इस कहानी का कोई सबूत नहीं है। लेकिन आसपास के लोग यही बताते हैं।

तारामती बारादरी सनसेट देखने के लिए बहुत खास जगह है। यहां से सनसेट के दौरान बहुत कमाल के नजारे दिखते हैं। शाम के समय डूबते हुए सूरज का दृश्य इस स्थान को और भी रोमांटिक बना देता है। कपल्स भी यहां समय बिताने के लिए आते हैं। हैदराबाद के लोग इस जगह को खास मानते हैं। उनका कहना है कि तारामती बारादरी मंडप देखे बिना हैदराबाद की ट्रिप अधूरी है।

तारामती बारादरी में 500 लोगों की क्षमता वाला एक एयर-कूल्ड थिएटर, 1600 लोगों की क्षमता वाला ओपन-एयर ऑडिटोरियम, 250 लोगों की क्षमता वाला बैंक्वेट हॉल, शानदार रेस्तरां और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तारामती बारादरी इब्राहिम बाग में स्थित है। आप टोली चौक से बस या ऑटो लेकर यहां पहुंच सकते हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 18 किमी है, जबकि नजदीकी मेट्रो स्टेशन माधवपुर से यह 15 किमी दूर है।

अमेठी कांड: क्या धोखे से दर्ज की गई एफआईआर? मृतक दलित टीचर के पिता के पुलिस पर आरोप से नया मोड़

आर्यावर्त संवाददाता

अमेठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दलित टीचर परिवार की हत्या मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, टीचर सुनील भारती के पिता ने आरोपी चंदन वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। लेकिन पिता राम गोपाल का कहना है कि उन्होंने पुलिस में अबतक कोई शिकायत नहीं की है, पुलिस ने कैसे ये मुकदमा दर्ज किया, ये उन्हें पता नहीं है। पिता के इस आरोप से अब पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है।

मृतक सरकारी टीचर सुनील के पिता राम गोपाल ने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने अंधेरे में रखकर उनके नाम से तहरीर लिख ली। इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वह अनपढ़ हैं। राम गोपाल ने बताया कि उनकी किसी से कोई

रंजिश नहीं थी। बहू-बेटे की हत्या के बाद अब कोई सहारा नहीं है। अगर छोटे बेटे को सरकार नौकरी दे देती तो उसी के सहारे जिंदा रहते।

प्राथमिकी में क्या है?

पुलिस के मुताबिक, मृतक सुनील के पिता राम गोपाल ने आरोपी चंदन वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस प्राथमिकी में राम गोपाल के हवाले से लिखा है कि उसका बेटा सुनील अमेठी के सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। वह परिवार के साथ वहां किराए के मकान में रहता था। कुछ दिन पहले रायबरेली में सुनील और चंदन वर्मा नाम के युवक के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान बहू पूनम भी वहीं थी। उसी रंजिश को लेकर चंदन वर्मा ने मेरे बेटे और उसके परिवार को मार डाला। इसी विवाद में गुरुवार की शाम सवा सात बजे चंदन वर्मा ने मेरे बेटे सुनील, बहू पूनम और दो बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी।

कौन हैं चंदन वर्मा?

एसपी अनूप सिंह के मुताबिक, 18 अगस्त को सुनील की पत्नी पूनम बच्चे के इलाज के लिए रायबरेली गई थी। इसी दौरान आरोपी चंदन वर्मा के खिलाफ स्थानीय थाने में छेड़खानी, गाली-गलौज और धमकी देने का केस दर्ज कराया था। पुलिस को शक है कि अमेठी में चार हत्याओं से कहीं न कहीं चंदन वर्मा भी लिंक है।

घर में घुसकर मारी गई गोली

गुरुवार को अमेठी में घर में घुसकर सरकारी टीचर सुनील भारती, पत्नी पूनम और उनके दो बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, तीन गोलियां सुनील को मारी गई थीं। इसके अलावा दो गोलियां पूनम को और एक-एक गोली बच्चों को मारी गई थी।

सुनील के पिता के बयान ने पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है। सवाल ये कि क्या पुलिस ने मृतक के पिता को धोखे में रखकर ये प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि, आशंका जताई जा रही है कि पिता राम गोपाल डर या दबाव की वजह से ऐसा कह रहे हैं।

'पांच लोग मरेंगे...', चंदन ने हत्याकांड से पहले वॉट्सऐप पर लगाया था स्टेटस, पुलिस ने एक संदग्धि को उठाया

अमेठी। अमेठी में शिक्षक सुनील, उनकी पत्नी और दो बच्चियों की हत्या ने पूरे प्रदेश को हलिाकर कर लयिा। इस हत्याकांड में शुक्रवार को बड़ा खुलासा हुआ है। रायबरेली के जसि चंदन वर्मा के नाम पर सुनील की पत्नी पूनम ने छेड़खानी और एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था, उसने अपने वॉट्सऐप स्टेटस पर पांच लोगों की हत्या करने की बात लखिी थी। चंदन का वॉट्सऐप स्टेटस वायरल हो रहा है, जसिमें अंग्रेजी में लखिा है, "5 People are going to die, I will show you soon" (5 लोग मरने वाले हैं, मैं तुम्हें जल्द ही दखिाऊंगा)।

हत्याकांड में अहोरवा भवानी निवासी एक संदिग्ध दीपक सोनी को रात में पुलिस ने उठाया है। बताया जा रहा है कि दीपक से चंदन की बात होती थी। दीपक कस्बे में मोबाइल की दुकान चलाता है।

यूपी के अमेठी में शिक्षक सुनील कुमार जिले के शिवरतनगंज कस्बे में परिवार के साथ रहते थे। गुरुवार की शाम सात बजे सुनील अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में ही थे। शाम करीब सात बजे बाइक पर सवार वहां पहुंचे और सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती और पांच वर्षीय पुत्री सृष्टि व डेढ़ वर्षीय बेटी लाडो पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। गोलियों की आवाज सुनकर लोग दौड़े लेकिन हमलावर भाग निकले। भीतर जाकर लोगों ने देखा तो चारो लथपथ पड़े थे। लोगों ने तत्काल घायलों को पास के सिंहपुर सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। शिक्षक सुनील, पत्नी पूनम व दोनों बच्चों के शवों का अमेठी में पोस्टमार्टम के बाद उन्हें रायबरेली के गदागंज थाना के सुदामापुर गांव लाया गया। शवों के पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। मृतकों के परिवारजन की चीत्कार से गांव में सभी दहल गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।

शादी का किया वादा... फिर सालों तक बनाया संबंध, कोर्ट बोला- ये रेप नहीं

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम संबंधों में आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों के लेकर फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने श्रेय गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 12 साल तक बनाए गए दोनों पक्षों की सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को इस आधार पर रेप नहीं कह सकते हैं कि युवक और युवती के बीच शादी नहीं हुई है.

कोर्ट ने रेप और जबरन वसूली के आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए कहा कि 12 साल से ज्यादा समय तक सहमति से चलने वाले संबंध को केवल शादी करने के वादे के उल्लंघन के आधार पर रेप नहीं माना जा सकता है. कोर्ट ने सहमति की कानूनी व्याख्या, झूठे बहाने के तहत यौन शोषण के आरोपों पर लम्बे समय तक संबंधों के प्रभाव पर भारतीय कानून में सहमति से यौन संबंध और रेप के बीच अंतर को परिभाषित कर याची को राहत दी, उसके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया.

पति की मौत के बाद भी चलता रहा रिश्ता

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया, जिस दौरान उसका पति गंभीर रूप से बीमार था, उस दौरान याची श्रेय गुप्ता ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. उसने यह कहकर ऐसा रिश्ता लगातार बनाए रखा. उसके पति की मौत के बाद उससे शादी कर लेगा. महिला के अनुसार, उसके पति की मौत के बाद भी ये रिश्ता जारी रहा, लेकिन याची ने आखिरकार 2017 में दूसरी महिला से सगाई कर ली. याची की इसी वायदा खिलाफी को आधार बनाकर महिला ने इस शख्स पर बलात्कार समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया है. पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसके बाद पुरुष ने हाईकोर्ट में अपील की है, जिसमें हाईकोर्ट ने उसे राहत दे दी है.

सभी क्रय केन्द्रों पर मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये-अभिषेक आनंद

सीतापुर। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में धान खरीद वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये धान की कस्टम हलिंग एवं सी0एम0आर0 सम्प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में जनपद के राइस मिलर के साथ बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि मिलों की ऑनलाइन फीडिंग और दूरी लॉक किये जाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करा ली जाये तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा विंग पोर्टल एवं सीएमआर प्राप्त किए जाने की तैयारी पूर्ण करा ली जाए। राइस मिलर अग्रिम लॉट सम्प्रदान की तैयारी कर लें तथा क्रय सत्र दौरान खरीदे गए धान के सापेक्ष समय से सी0एम0आर0 सम्प्रदान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी क्रय केन्द्रों पर मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये।

'आवाज निकाली तो कर दूंगा सौदा...', धमकाकर 4 साल तक बेटी से रेप, मां ने 6 साल कानूनी लड़ाई लड़कर पति को पहुंचाया जेल

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपनी ही नाबालिग बेटी से रेप करने के मामले में पिता को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया। आरोपी शख्स ने पूरे चार साल तक सौतेली बेटी से हैवानियत की। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कहा- इसे 20 साल कैद की सजा सुनाई जाती है।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी पिता 2014 से 2019 के बीच नोएडा फेज-3 स्थित घर में अपनी 14 साल की नाबालिग सौतेली बेटी का रेप करता रहा। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए गुरुवार को सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) जेपी भाटी के अनुसार, इस घटना की सूचना मई 2019 में पीड़िता की मां ने पुलिस को दी थी।

जेपी भाटी ने बताया, 'शिकायतकर्ता की पहली शादी से तीन बच्चे- दो बेटे और एक बेटी है। नवंबर 2008 में उसके पति की मौत हो गई, जिसके बाद उसने 15 अप्रैल 2012 को दूसरी शादी कर ली। पांचों सदस्य फेज-3 थाने के अंतर्गत एक इलाके में रहते थे। शिकायतकर्ता एक फैक्ट्री में काम करती थी, जबकि उसका दूसरा पति बेरोजगार था और बच्चों के साथ घर पर रहता था।'

18 मई 2019 को फेज-3 थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया, 'मेरे पति ने मेरे बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया और उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। 15 मई 2019 को मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसने उसका यौन शोषण किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे कोठे में बेच देगा और मुझे मार देगा।' शिकायतकर्ता ने कहा, 'उसके आचरण और व्यवहार से दुखी होकर मैं आगरा में अपने पैतृक घर आ गई और अपने माता-पिता को सारी बात बताई। हिम्मत जुटाकर मैंने तीन दिन बाद अपने पति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।'

'कोठे में बेच दूंगा तुझे'

आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की रेप, आपराधिक धमकी, जानबूझकर अपमान और हमला एवं पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उसे 18 मई, 2019 को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसके सौतेले पिता ने चार साल तक उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने कहा, 'सौतेले पिता ने पहली बार मेरा रेप तब किया जब मैं 11 साल की थी। जब मेरी मां काम पर जाती थी, तो वह मेरे भाई को बाहर भेज देता था और मेरा यौन शोषण करता था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह मुझे कोठे पर बेच देगा और मेरे भाइयों एवं मां को मार देगा।'

शराब की दुकान में निकले नाग-नागिन, देख भाग खड़ा हुआ दुकानदार... एक को पकड़ा, दूसरा बिल में घुसा

आर्यावर्त संवाददाता

औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब औरैया कोतवाल के सुभाष चौक के पास बियर ठेका में मिले सांपों के जोड़े से दुकान पर बैठे गद्दीदार समेत बियर लेने आए शराबियों के होश उड़ गए। गद्दीदार ने इसकी सूचना दुकान मालिक को दी। दुकान मालिक ने तत्काल वन विभाग के रेंजर को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बियर की दुकान पर रेस्क्यू कर एक सांप को मौके से पकड़ा लिया, जबकि दूसरा सांप बिल में घुस जाने की वजह से वन विभाग की टीम से वो बचा रह गया।

औरैया जिले के सुभाष चौराहे के पास स्थित बियर ठेका पर जब बियर की दुकान पर बैठकर सेल्समैन बिक्री कर रहा था, तभी उसे आचनक आभास हुआ कि गद्दी के नीचे कुछ है।

जैसे ही सेल्समैन ने नीचे देखा तो सेल्समैन के होश उड़ गए। सेल्समैन ने देखा एक जोड़ा नाग-नागिन का नीचे बैठा हुआ है, तभी सेल्समैन ने अपने दुकान के मालिक मंजुल पांडे को इसकी सूचना दी। वहीं आसपास के दुकानों के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। डर के कारण कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।

सांप बिल में घुस गया

दुकान में सांपों का जोड़ा देखकर, दुकान मालिक ने तत्काल घटना की जानकारी वन विभाग की टीम को दी। वन विभाग की टीम भी वहां कुछ ही पल में पहुंच गई। बियर की दुकान में भीड़-भाड़ वाले इलाके में होने के कारण लोग काफी डरे हुए थे। तभी, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू आपरेशन चलाया गया, जिसमें एक सांप को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके पकड़ लिया।

एक सांप को जैसे ही रेस्क्यू टीम ने पकड़ लिया, वहीं दूसरा सांप बिल के अंदर जाकर छिप गया। इसके देखकर वन विभाग की टीम ने काफी देर तक रेस्क्यू चलाया, लेकिन बिल में घुसे हुए सांप को बाहर नहीं निकाल पाए। वहीं अब दूसरे सांप के निकलने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही सांप बाहर निकलेगा वैसे उसे पकड़ लिया जाएगा। कहीं दूसरा सांप किसी को काट न ले इसके लिए लोग उसे पकड़वाकर वन विभाग की टीम को सौंपना चाहते हैं।

नागिन को पकड़ा, नाग बिल में घुसा

वन विभाग की टीम ने नागिन को पकड़ लिया। वहीं नाग बिल के अंदर जाकर घुस गया। अब दुकान के मालिक और वन विभाग की टीम निकलने का इंतजार कर रही है। दूसरे सांप का भी रेस्क्यू करने का आश्वासन वन विभाग की टीम के तरफ से दिया गया है।

चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो शातिर चोरो को बनाया बंदी

लहरपुर /सीतापुर। कोतवाली क्षेत्र के पोंगलीपुर नहर पुल के निकट कोतवाली पुलिस ने दो शातिर चोरों को चोरी के लाखों रुपये मूल्य के सोने चांदी के आभूषणों सहित बनाया बंदी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा व पुलिस टीम के द्वारा सूचना के आधार पर रियाज पुत्र जलील नि0 ग्राम समोदीडीह थाना तम्बौर, हलीम पुत्र रसूल अहमद निवासी नई बस्ती मजरा समोदीडीह थाना तम्बौर को सामान्य वाहन चेकिंग के दौरान पोंगली पुर शारदा नहर पुल के पास से बंदी बनाया, पुलिस ने उनके पास से चोरी के ताबीज सफेद धातु के 27 नग, शुभ लाभ सफेद धातु के 12 नग, अंगुठी सफेद धातु 40 नग, कड़ा सफेद धातु के 08 नग, पायल सफेद धातु के कुल 71 नग, कमर बन्द सफेद धातु के 02 नग, बिछिया 218 नग सफेद धातु, राखी पांच अदद सफेद धातु के, मोती माला 32 नग, लाकेट छोटे बडे 02 अदद पीली धातु, 06 अदद झुमकी छोटी बड़ी पीली धातु बरामद किया।

ग्रीनफील्ड फोरलेन सड़क के लिए NHAI ने खोजे तीन रूट, यूपी के इन जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा

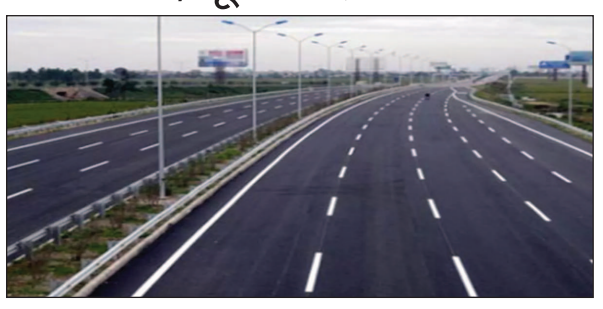

आर्यावर्त संवाददाता

वाराणसी। गाजीपुर वाया जमानियां से सैयदराजा (चंदौली) तक नई ग्रीनफील्ड फोर लेन सड़क बनाने की स्वीकृति मिली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने तीन रूट तलाशे हैं, इसमें पहला 65 किलोमीटर, दूसरा 60 किलोमीटर जबकि तीसरा रूट करीब 40 किलोमीटर लंबा है।

तीनों रूटों का सर्वे हो चुका है। दिल्ली की कंपनी कास्टा की तरफ से रिपोर्ट एनएचएआइ मुख्यालय नई दिल्ली को भेजी गई है। अब शीर्ष अधिकारी तीनों में से कोई एक रूट फाइनल करेंगे और प्राधिकरण स्थानीय स्तर पर संबंधित रूट का डीपीआर बनाएगी।

सड़क का एलाइनमेंट फाइनल करने की मंशा से प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इस डिजिटल प्लेटफार्म पर देश के 16 मंत्रालयों का समन्वय होता है। सड़क व रेलवे समेत कई विभागों के विशेषज्ञ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का हिस्सा होते हैं, वे प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देंगे। साथ ही परियोजना में संभावित बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रोजेक्ट पर करीब 2700 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है, इसमें करीब आठ सौ करोड़ रुपये जमीन खरीदने पर खर्च किया जाएगा।

जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर में बनेगा दो लेन का बाईपास, सर्वे शुरू

एनएचएआइ पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी संतोष कुमार आर्य ने बताया कि जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर में दो लेन का बाईपास बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रोजेक्ट की लागत करीब सौ करोड़ आएगी। इस बाईपास को प्रयागराज रोड और रायबरेली रोड को आपस में लिंक किया जाएगा।

सर्वे शुरू कर दिया गया है। प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद वाहनों को मुंगराबादशाहपुर निकाय क्षेत्र में प्रवेश करने की जरुरत नहीं होगी। वह बाहरी क्षेत्र से ही आवागमन कर सकेंगे।

कहानी देहाती रसगुल्ले की... जिसे बेचकर करोड़पति बन गए प्रयागराज के यादव जी

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सिर्फ संगम और एजुकेशन के हब के लिए ही नहीं जाना जाता है, इस शहर के जायके ने भी लोगों का दिल जीता है। इतना बेहतरीन स्वाद कि इसका नाम आते ही मुंह में पानी आ जाए। यहां के नेतराम की स्वादिष्ट और चटपटी कचौड़ी खाने के बाद अगर आपको मुंह मीठा करने का मन करे तो शहर के देहाती रसगुल्ले का स्वाद आपके मन में मिठास घोलने के लिए काफी है। इसे खाकर आप भी कह उठेंगे वाह! मजा आ गया।

प्रयागराज में मिष्ठान के शौकीन लोगों के लिए शहर का लोकनाथ और बैरहना इलाका उनके पसंदीदा जगहों में से एक है। लोकनाथ अगर यहां की रबड़ी लस्सी के लिए ट्रेड मार्क बन गया है तो बैरहना मुहल्ला देहाती रसगुल्ले का... 39 साल पुरानी रसगुल्ले की इस दुकान में शाम को इसका स्वाद लेने के लिए कई बार लंबी-लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। इसके लजीज स्वाद से आप रूबरू हों

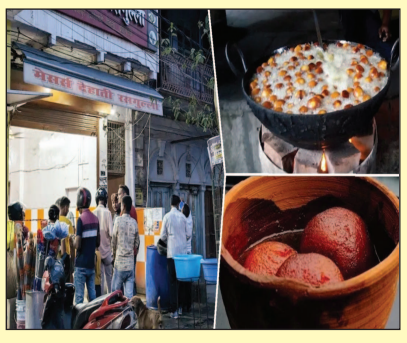

इससे पहले इसके नाम के पीछे की वजह जानते हैं, आखिर इसे देहाती नाम कैसे मिला?

कैसे पड़ा रसगुल्ले का देहाती नाम?

प्रयागराज के बैरहना मोहल्ले में 39 साल पहले दूध का धंधा करने वाले राम स्वरूप यादव ने छोटी सी मिठाई की दुकान खोली। इस दुकान पर बनाए गए रसगुल्ले का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया। कम मिठास , शुद्धता और सॉफ्टनेस की वजह से लोग इसके जायके के मुरीद होते चले गए। अब रसगुल्ले को लेकर लोगों की बढ़ती पसंद को लेकर, रामस्वरू ने अब सारी मिठाइयां बंद कर दीं। उन्होंने अपना फोकस रसगुल्ले पर ही रखा। देखते ही देखते कुछ समय में रामस्वरूप की दुकान पर रसगुल्ले की डिमांड बढ़ती चली गई। अब बिक्री तो हो रही थी, लेकिन रामस्वरूप के रसगुल्ले को एक पहचान की जरूरत थी। राम स्वरूप यादव के बेटे अजय यादव का कहना हैं कि उनके पापा को उनके दोस्त प्यार से 'देहाती' बुलाते थे, क्योंकि वह देहात से आते हैं। ऐसे में अपनी रिहायशी पहचान को उन्होंने रसगुल्ले को दे दिया और उनके स्वादिष्ट रसगुल्ले का नाम देहाती रख दिया गया। अब तो प्रयागराज में देहाती रसगुल्ला एक ब्रांड बन गया है।

इसमें इतना स्वाद आखिर क्यों है?

जुबान को लजीज स्वाद का कायल बना देना आसान बात नहीं होती है और वो भी रसगुल्लों की दौड़ में जहां कई फ्लेवर स्वाद का ऑप्शंस मौजूद होता है। ऐसे में प्रयागराज में देहाती रसगुल्ला ने लोगों के स्वाद में अपनी स्वाद कैसे छोड़ दी है? इसके बारे में देहाती रसगुल्ला के दुकानदार विजय यादव ने बताया है।

उन्होंने इसमें इस्तेमाल किए गए खास इन्ग्रीडीयंट्स के बारे में बताया है। वैसे तो रसगुल्ला अमूमन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला खोवा, दूसरा चीनी और तीसरा मैदा। इन तीनों का मिलाने का अनुपात और मिलाने का अंदाज इसके स्वाद को अलग बना देता है। अजय के मुताबिक, वह बनाने की सामग्री से समझौता नहीं करते हैं। वो रसगुल्ले में खुद से बनाए गए या भरोसेमंद लोगों से लिए हुए खोवा का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो कहीं और से खोवा ले रहे हैं तो टेस्ट करके उसके स्वाद की जांच करवाते हैं।

कैसे आती है इस रसगुल्ले में सॉफ्टनेस?

अब बात आती है रसगुल्ले की सॉफ्टनेस की तो यही उनकी यूएसपी है। आमतौरपर मिठाई भंडार वाले एक किलो खोवा में 500 से 600 ग्राम मैदा मिलाते हैं, जिसके बाद उनका मुनाफा बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा करने से उनका रसगुल्ला देहाती रसगुल्ले जैसा नहीं बन पाता है, क्योंकि मैदा मिलाने से रसगुल्ला सख्त हो जाता है। साथ ही स्वाद पर भी असर पड़ता है। हम अपने यहां 1 किलो खोवा में सिर्फ 150 ग्राम मैदा ही मिलाते हैं। इससे रसगुल्ला इतना सॉफ्ट बनता है कि मुंह में डालते ही घुल जाए।

कीमत भी पॉकेट फ्रेंडली, 75 लाख का टर्नओवर

दुकानदार अमित बताते है कि एक दौर था कि जब हमने इसकी शुरुआत 1 रुपए से की थी। समय बीता और जब महंगाई बढ़ी तो दूध के रेट बढ़े इस कारण रसगुल्ले के रेट भी बढ़ाने पड़े। अब एक देहाती रसगुल्ला की कीमत 20 रुपए हैं। यह आम रसगुल्लों की तुलना में डबल साइज का रहता है। यहां हर रोज करीब 3 से 4 हजार रसगुल्ला बिक जाता है। देहाती रसगुल्ले का सालाना टर्नओवर करीब 75 लाख रुपए का है।

विदेशी पर्यटकों को भी है बहुत पसंद

इस देहाती डिश के दीवाने दूसरे शहरों के पर्यटक ही नहीं, बल्कि विदेशी टूरिस्ट भी हैं। रसगुल्ले की ये खास दुकान वैसे तो शहर के पॉश इलाके से हटकर संगम क्षेत्र के नजदीक बनाई गई है, लेकिन विदेशों से आने वाले ट्यूरिस्ट भी यहां तक खिंचे चले आते हैं। कुंभ मेला या माघ मेला में आने वाला तीर्थ यात्री इसका जायका लिए बिना शायद ही जाता हो। वैसे थाईलैंड, कनाडा, ब्रिटेन ,नेपाल और पोलैंड के पर्यटक यहां अक्सर आते हैं। इस बार तो महाकुंभ में इसके स्टॉल कुंभ क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों का जायका बढ़ाएंगे।

वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर मारने वाला भागलपुर का हुसैन गिरफ्तार, यात्रियों का मोबाइल छीनना था मकसद

आर्यावर्त संवाददाता

वाराणसी। वंदे भारत पर पत्थरबाजी कर सनसनी फैलाने का आरोपित मो. हुसैन उर्फ शाहिद को एटीएस ने बुधवार को पकड़ लिया। उसने पूछताछ में स्वीकारा कि ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने के पीछे एक ही मकसद यात्रियों का मोबाइल छीनना होता है। बताया कि पत्थरबाजी करने पर ट्रेन की रफ्तार कम हो जाती है, जिसके बाद वह खिड़की के पास बैठे व्यक्ति का मोबाइल छीनकर भाग निकलता है।

व्यासनगर व काशी स्टेशन क्षेत्र में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की कई घटनाएं हुई। घटनाओं के संबंध में आरपीएफ ने मुकदमा दर्ज किया था। छानबीन में पत्थरबाजी का एक आरोपित पवन कुमार साहनी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि उसका साथी इशहाकचक (भागलपुर बिहार) का मो. हुसैन उर्फ शाहिद हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था।

एटीएस जुटी तो पता चला कि मो. हुसैन चंदौली जिले के पड़ाव अंतर्गत चौरहट में किराये का कमरा लेकर रहता है। एटीएस उसे उठाकर लाई और पूछताछ की तो उसने ट्रेन पर पत्थर मारने की घटना करना स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे रेलवे सुरक्षा बल, व्यासनगर के सुपुर्द कर दिया गया।

कहीं आप भी तो नहीं पैरेंटल बर्नआउट के शिकार, जानिए इससे निपटने के तरीके

कई माता-पिता बच्चों की देखभाल में इतना खो जाते हैं कि खुद को समय नहीं दे पाते। लगातार जिम्मेदारियों का बोझ उन पर हावी हो जाता है और वे बच्चों के लिए कुछ न कर पाने का दोष भी खुद को देने लगते हैं।

कई पैरेंटस तो बच्चों की परवरिश में इतना डूब जाते हैं, कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते और अवसाद, तनाव जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है पैरेंटल बर्नआउट की। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें 66 प्रतिशत वर्किंग पैरेंटस अपने बच्चों की देखभाल से इतना थक जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है।

राज एक्सप्रेस। क्या आप भी एक बच्चे के माता-पिता हैं। अगर हां, तो जिम्मेदार माता-पिता की तरह अपने बच्चे की हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास करते होंगे। कई पैरेंटस तो बच्चों की परवरिश में इतना डूब जाते हैं, कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते और अवसाद, तनाव जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है पैरेंटल बर्नआउट की। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें 66 प्रतिशत वर्किंग पैरेंटस अपने बच्चों की देखभाल से इतना थक जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। कोई भी माता पिता पैरेंटल बर्नआउट का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह पैरेंटिंग का ही एक हिस्सा है, इसलिए वे इसे किसी के साथ शेयर नहीं करते । लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाना मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अगर आप भी पैरेंटल बर्नआउट की गिरफ्त में हैं, तो यहां बताया गया है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं।

पैरेंटल बर्नआउट के लक्षण

शारीरिक या भावनात्मक थकावट का अनुभव करना।

अपनी पैरेंटिंग को लेकर शर्मिंदगी महसूस करना, या यह सोचना कि वे उतने अच्छे माता-पिता नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे।

माता-पिता होने की भूमिका से तंग आ जाना।

अपने बच्चों से भावनात्मक रूप से अलग महसूस करना।

पैरेंटल बर्नआउट के कारण

काम का बोझ

हर माता-पिता को एक समय पर कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। ऐसे में वह बिना आराम किए लगातार काम करते हैं। यह बर्नआउट का कारण बन सकता है।

सपोर्ट न होना

आज भी महिलाओं के काम को तवज्जो नहीं दी जाती और न ही कोई उन्हें सपोर्ट करता है। वर्किंग मदर के लिए तो यह और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनके पास बच्चों की देखभाल करने वाला या काम में हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में वह बर्नआउट की शिकार हो सकती है।

तारीफ न मिलना

घर की जिम्मेदारी को ठीक से निभाने के बाद भी जब तारीफ न मिले, तो महिला का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और बर्नआउट के रूप में सामने आता है।

बर्नआउट तनाव से कैसे अलग है

कई लोग बर्नआउट को तनाव समझ लेते हैं, लेकिन बता दें कि बर्नआउट एक लंबे समय तक चलने वाली स्थिति है। जबकि तनाव अस्थाई है। तनाव अधिक सक्रियता का कारण बनता है, जबकि बर्नआउट लाचारी और निराशा का कारण है। तनाव से चिंता विकार और अवसाद हो सकता है जबकि बर्नआउट आमतौर पर अवसाद से जुड़ा हुआ है।

पैरेंटल बर्नआउट से कैसे बचें

खुद के लिए समय निकालें

पैरेंटस के रूप में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अपना 100 प्रतिशत नहीं दे रहे हैं। इस जगह हम न केवल तनाव महसूस करते हैं, बल्कि हमें असफलताओं का अनुभव भी होता है। ऐसे में खुद को दोष न दें , बल्कि अपने लिए थोड़ा समय निकालें। एक शोध से पता चला है कि जो माता-पिता खुद की देखभाल को प्राथमिकता देते हैं, उनका समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है।

मदद लें

ऐसी कई चीजें हैं, जो बर्नआउट में योगदान देती हैं। इनमें समर्थन की कमी, जिम्मेदारी का उच्च स्तर, वर्कप्लेस की टेंशन, बूढ़े माता-पिता की देखभाल और वित्तीय चिंताएं शामिल हैं। माता-पिता के लिए बर्नआउट के संकेतों की पहचान करना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना जरूरी है। आमतौर पर महिलाएं पर ही बच्चों के देखभाल की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उनके जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों को उनके बर्नआउट के संकेतों पर नज़र रखनी चाहिए और उनके कहे जाने से पहले ही उनकी मदद करनी चाहिए।

पॉजिटिव पैरेंटिंग स्ट्रेटजी अपनाएं

हेल्दी पैरेंटिंग स्ट्रेटजी को अपनाने से आप इस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट के लिए अपने साथी और करीबी दोस्तों से बात करें। आप चाहें, तो एक मॉम ग्रुप जॉइन कर सकती हैं। यहां आपको अपनी पैरेंटिंग प्रॉब्लम को शेयर करने के साथ इस पर दूसरों के विचार जानने को मिलेंगे।

काम से जुड़े बदलाव करें

प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ बदलाव करने से पैरेंटल बर्नआउट को कम करने में मदद मिल सकती है। वर्क फ्रॉम होम या फिर ऐसी जॉब चुनें, जहां आपको कुछ ही घंटे काम करना हो। ऐसे में आप अपने काम, बच्चों और परिवार के बीच बेहतर संतुलन बना पाएंगे ।

हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं

हर रात कम से कम सात घंटे की नींद लें। किसी भी कंडीशन में ब्रेकफास्ट स्किप न करें और जंक फूड से दूर रहें। रैगुलर वर्कआउट करना भी जरूरी है। यह बर्नआउट के लिए एक पॉवरफुल एंटीडोट है।

पैरेंटिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपको अपने काम के लिए सराहना, मान्यता और समर्थन नहीं मिलता, तो आप थक सकते हैं और बर्नआउट के शिकार हो सकते हैं। पैरेंटिंग का भी अपना मजा है। इसलिए बर्नआउट के दबावों को दूर करने कैे लिए यहां बताए गए तरीके अपनाएं और खुश रहें।

रात को सोने से पहले भी रखें त्वचा का ध्यान, जानिए क्यों जरूरी है नाइट स्किन केयर

अपनी फिजिकल हेल्थ की तरह त्वचा का ख्याल रखना भी जरूरी है। लोग दिन के समय ही अपनी त्वचा का ध्यान रखते हैं लेकिन नाइट स्किन केयर भी बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि रात के समय स्किन केयर क्यों जरूरी है।

सुबह उठने के बाद हम सभी स्किन केयर रुटीन को फॉलो करते हैं। इससे स्किन पूरा दिन हेल्दी और ग्लोइंग रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना जरूरी मॉर्निंग स्किन केयर रुटीन है, उतना ही जरूरी नाइट स्किन केयर भी है। स्किन एक्सपर्ट कहते हैं कि रात को सोने से पहले भी त्वचा पर ध्यान देना जरूरी है।

पूरे दिन स्किन धूप और प्रदूषण के संपर्क में आती है, जिसके चलते त्वचा बेजान और डल नजर आ सकती है। स्किन केयर रूटीन सिर्फ एक ब्यूटी ट्रेंड नहीं है बल्कि आपकी स्किन को हेल्दी और नमी युक्त रखने का एक सीक्रेट भी है। आइए जानते हैं कि रात के समय स्किन केयर रुटीन जरूरी है।

स्किन होती है रिपेयर

रात के समय हमारा पूरा शरीर रिपेयरिंग मोड में चला जाता है। इसके कारण स्किन प्रदूषण और सूरज की हानिकारक यूवी किरणों के नुकसान से उबर पाती है। ऐसे में रात के समय स्किन पर उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जो सेल टर्नओवर पर फोकस रखते हैं। इस समय आप रेटिनॉल जैसी चीजों को अप्लाई करेंगे।

कोलेजन बूस्ट

रात के समय आपका शरीर ज्यादा मात्रा में कोलेजन बनाता है। ये स्किन इलास्टिसिटी में जरूरी है। ये त्वचा में झुर्रियां कम करने में मदद करता है। रात के समय कोलेजन बढ़ाने वाले वाले प्रोडक्ट्स जैसे- रेटिनॉल का इस्तेमाल कर सकती है। इससे स्किन जवां और हेल्दी नजर आती है।

खुद को रखें हाइड्रेट

त्वचा का ख्याल रखने के लिए जरूरी है कि आप जितना हो सके, खुद को हाइड्रेट रखें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इससे त्वचा में नमी बरकरार रहेगी और शरीर में टॉक्सिंस बाहर निकलेंगे।

विटामिन हैं जरूरी

इसके अलावा, त्वचा के लिए कुछ विटामिन भी जरूरी हैं। डाइट में विटामिन ए, बी12, सी और डी से भरपूर चीजों को शामिल करें। इससे एक्ने-पिंपल, फाइन लाइन्स और झुर्रियों से राहत मिलती है।

रात को सोने से पहले स्किन केयर रूटीन में त्वचा को मॉइश्चराइज करना बेहद जरूरी है। आप रात के समय हाइलूरोनिक एसिड वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे स्किन में हाइड्रेशनलॉक रहता है।

क्या आपको भी है रात में जागने की आदत, तो जान लें इससे होने वाले ये गंभीर नुकसान

दिनभर की थकान के बाद कई लोग बिस्तर पर जाते ही सो जाते हैं तो वहीं कुछ लोगों को जल्दी नींद ही नहीं आती। ऐसे में वो देर रात तक जागते हैं। कई लोगों को ऑफिस के काम की वजह से भी रात में जागना पड़ता है लेकिन क्या आप जानते हैं इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है?

अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं तो नाइट आउल हूं, यानी वे लोग जो रात में जागकर काम या मूवी आदि देखना पसंद करते हैं। आजकल अधिकतर लोग खासकर यंगस्टर रात में जागते हैं। कई बार ऑफिस के काम की वजह से भी लोग रात में जागकर उसे पूरा करने की कोशिश रहते हैं। ऐसे में लोग पर्याप्त नींद भी नहीं ले पाते हैं, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ता है।

सेहत को लेकर ऐसी लापरवाही कई बीमारियों को जन्म देती हैं। स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद सोना चाहिए। इससे कम सोने वाले लोगों को मोटापा, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द आदि की समस्याओं से जूझना पड़ता है। अगर आप भी ये गलती करते हैं, तो आपको बता दें कि आप अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं।

आयु होती है कम

पर्याप्त नींद नहीं लेने से आयु कम होती है। दक्षिण कोरिया में 16 सालों तक किए गए एक शोध के अनुसार जो लोग रात में ज्यादा देर जागना पसंद करते थे, उन्हें कम उम्र में ही अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। यह शोध 40 से 69 उम्र के लोगों के बीच में किया गया था।

दिमाग पर पड़ता है असर

जो लोग रात में ज्यादा देर तक जागते हैं, उन्हें मेमोरी लॉस, डिसीजन मेकिंग आदि में समस्या का सामना करना पड़ता है। देर से सोने वाले लोगों में मूड स्विंग भी देखे जा सकते हैं।

वजन बढ़ना

कई बार देखा गया है कि जो लोग रात में कम सोते हैं, उन लोगों में वजन बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे लोग जल्दी वेट गेन कर लेते हैं क्योंकि वजन बढ़ने का एक कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिससे सेहत बिगड़ती है।

इम्युनिटी कम होती है

जो लोग रात में पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, उन लोगों की इम्युनिटी लो रहती है, जिससे वे जल्द बीमार पड़ते हैं। इसलिए रात में पर्याप्त नींद लें ताकि शरीर स्वस्थ रहे।

एसबीआई की नई सेविंग स्कीम, आरडी और एसआईपी का मिलेगा फायदा

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा इन्वेस्टमेंट के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है। लोगों के बीच बैंक की एफडी स्कीम काफी पॉपुलर है। अब बैंक निवेश के लिए नया प्रोडक्ट लाने की प्लानिंग कर रही है। इस नए प्रोडक्ट की जानकारी एसबीआई के चेयरपर्सन ने दी है। इस स्कीम में कस्टमर को आरडी और एसआईपी का फायदा मिलेगा।

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) निवेश के लिए कई स्कीम चला रही है। अब बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए नया प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही है। इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेशक को रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी)और एसआईपी (एसआईपी) दोनों का लाभ मिलेगा।

एसबीआई की इस प्रोडक्ट की जानकारी बैंक के चेयरमैन सी एस शेट्टी ने दी है। उन्होंने बताया कि बैंक निवेश के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने की प्लानिंग कर रही है। यह प्रोडक्ट देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति के साथ ही कस्टमर को फाइनेंशियल तौर पर जागरूक करने के लिए बनाया जाएगा।

आज भले ही लोग निवेश की महत्वता को समझते हुए एसेट अलोकेशन की तरफ रुख कर रहे हैं। इसके बावजूद निवेशक रिस्क वाले एसेट में सबकुछ लगाना पसंद नहीं करते हैं। वह अगर रिस्क एसेट में निवेश करते हैं तो सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी सेलेक्ट करते हैं। निवेशक हर दिन निवेश के नए साधन की तलाश करते हैं।

पारंपरिक प्रोडक्ट का होगा नया वर्जन

निवेश की जब भी बात होती है अक्सर निवेशक बैंकिंग प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना पसंद करते हैं। निवेशकों को बैंक पर ज्यादा भरोसा रहता है। इसी भरोसे को कायम रखने के लिए एसबीआई अपने पारंपरिक प्रोडक्ट में नवीनता लाने की कोशिश करेगा। ऐसे में उम्मीद है कि बैंक आरडी या एसआईपी जैसे प्रोडक्ट का संयुक्त रूप ला सकता है। यह प्रोडक्ट डिजिटल रूप से सुलभ होगा। एसबीआई चेयरमैन सी एस शेट्टी ने कहा कि बैंक अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए नवाचारों पर विचार कर रही है।

फंड जुटा रही है बैंक

बैंक ने फंड जुटाने के लिए एक पहुंच कार्यक्रम शुरू किया है। फंड जुटाने के लिए बैंक एक फ्रेंचाइजी के तौर पर काम कर रही है। इसके लिए बैंक अपने सभी मौजूदा कस्टमर के साथ नए कस्टमर से संपर्क कर रही है।

अब एयर ट्रेन की बारी! दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू होगी सर्विस, कितना होगा किराया?

ट्रेन और हवाई जहाज के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा लेकिन क्या आपने कभी हवा में चलने वाली ट्रेन के बारे सुना है? अब कुछ ही सालों में भारत को पहली एयर ट्रेन मिलने जा रही है। इसका कितना किराया होगा...

साल 2028 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकमात्र ऊंचे टैक्सीवे पर विमानों के नीचे एक एयर ट्रेन चलने लगेगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने 7.17 किलोमीटर लंबी ऑटोमेटेड पीपल मूवर (APM) ट्रेन बनाने के लिए टेंडर जारी किया है। यह एयर ट्रेन टर्मिनल 2 और 3 को टर्मिनल 1 से जोड़ेगी। यह ट्रेन रनवे 28 के नीचे से होकर गुजरेगी।

एयर ट्रेन का अधिकतर हिस्सा ऊंचा होगा। इसमें 5.17 किमी ऊंचा रास्ता होगा और 2 किमी ज़मीन पर होगा। ज़मीन वाला हिस्सा टर्मिनल 1 के पास होगा और ऊंचे टैक्सीवे के नीचे होगा। कार्गो स्टेशन पर एक स्काईवॉक बनेगा, जो एयर ट्रेन को कार्गो टर्मिनल से जोड़ेगा।

कितनी है लागत?

DIAL ने खर्च कम रखने के लिए ट्रेन को जमीन के नीचे नहीं बनाने का फैसला किया है। भारत में ऊंची ट्रेन बनाने की औसत लागत 250-300 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर होती है। जब ट्रेन जमीन पर बनाई जाती है, तो इसकी लागत 150-200 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर होती है। अगर ट्रेन को जमीन के नीचे बनाया जाए, तो लागत 500-600 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर होती है। इसमें ट्रेन बनाने, सिग्नल, बिजली और बाकी सभी कामों की लागत भी शामिल है।

अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1,500-1,600 करोड़ रुपये हो सकती है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उड्डयन मंत्रालय ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए यात्रियों से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा। पहले हवाई अड्डे को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कहा गया, और बाद में पैसे वसूलने की सलाह दी गई।

कितनी होगी कीमत?

सरकार ने पहले एयर ट्रेन के लिए यात्रियों से पैसे लेने की योजना बनाई थी, लेकिन आमतौर पर दुनिया में एयर ट्रेनें मुफ्त होती हैं। इससे खर्च एयरलाइंस या दूसरी जगहों से वसूला जाता है। जैसे मुंबई हवाई अड्डे पर पहले घरेलू उड़ान के लिए 20 रुपये और अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए 120 रुपये का चार्ज लिया जाता था, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। इसलिए, DIAL को खर्च और संभावित कमाई का ध्यान रखते हुए बोलियों का सही मूल्यांकन करना होगा ताकि एयर ट्रेन का संचालन ठीक से हो सके।

सेबी के एक्शन से एफएंडओ सेगमेंट में आधी रह जाएगी ट्रेडिंग वॉल्यूम

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (एफएंडओ) को लेकर बनाए गए नए नियमों के लागू होने के बाद एफएंडओ सेगमेंट में ट्रेडिंग वॉल्यूम आधी हो सकती है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि वॉल्यूम में 50 प्रतिशत तक की गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ने के बाद 50 से 60 प्रतिशत ट्रेडर्स के बाजार से बाहर होने की उम्मीद है।

सूत्रों ने बताया कि अगर नए

नियम लागू होने के बाद डेरिवेटिव्स मार्केट की वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आता है तो सेबी आगे भी एक्शन ले सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेबी के एक्शन से फ्यूचर्स और ऑप्शन का औसत ट्रेड साइज वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 20,000 रुपये पर पहुंच सकता है, जो कि फिलहाल 5,500 रुपये पर है। सेबी ने बीते मंगलवार को एफएंडओ के नियमों को सख्त कर दिया गया था।

बाजार नियामक द्वारा अब इंडेक्स डेरिवेटिव में कॉन्ट्रैक्ट साइज की न्यूनतम वैल्यू को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही साप्ताहिक एक्सपायरी को प्रति एक्सचेंज एक इंडेक्स तक सीमित कर दिया है। ऐसे में अब एक एक्सचेंज की ओर से सप्ताह में एक ही एक्सपायरी देखने को मिलेगी।

सेबी की ओर से यह कदम रिटेल निवेशकों द्वारा डेरिवेटिव सेगमेंट में लगातार किए जा रहे नुकसान के कारण लिया गया है। हाल ही में बाजार नियामक द्वारा एक स्टडी जारी की गई थी। इसमें बताया गया था कि बीते तीन वर्षों में एफएंडओ सेगमेंट में 1.10 करोड़ ट्रेडर्स को संयुक्त रूप से 1.81 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

इसमें से केवल 7 प्रतिशत ट्रेडर्स ही पैसा कमाने में सफल हुए हैं। इसके कारण बाजार से जुड़े कई लोगों ने एफएंडओ नियमों को सख्त बनाने की बात कही थी। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स के नए नियम 20 नवंबर, 2024 से लागू हो जाएंगे।

'भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं बंद किया', पीयूष गोयल ने आतंकवाद-द्विपक्षीय संबंधों पर खुलकर की बात

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के दौरे पर गए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दो-टूक लहजे में कहा कि पाकिस्तान ने जब हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तब हमने उसका उचित जवाब भी दिया। दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने अपनी ओर से पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद नहीं किया है। पाकिस्तान ने खुद ही व्यापार बंद किया है।

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के मकसद से वाशिंगटन पहुंचे पीयूष गोयल ने पाकिस्तान के मसले पर कहा, "साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने पाकिस्तान के साथ देश के रिश्ते सुधारने को लेकर हर संभव कदम उठाए थे। पीएम मोदी ने साल 2014, 2015 और 2016 में पड़ोसी

मुल्क के साथ रिश्ते बेहतर करने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने यहां आतंकी गतिविधियां बंद नहीं करेगा। हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो यह स्वाभाविक है कि भारत उसका जमकर मुकाबला करेगा।"

हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो

जवाब देंगे: गोयल

सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उन्होंने कहा कि हमने वही किया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान की ओर से जब भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो हमने उसका माकूल स्तर पर जवाब दिया।

पाकिस्तान के साथ अटारी बॉर्डर पर व्यापार की संभावना पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, "जहां तक दोनों देशों के बीच व्यापार का सवाल है, भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार करना बंद नहीं किया है। पाकिस्तान ने खुद ही भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया है।" उन्होंने आगे कहा कि भारत ने कभी भी किसी देश के साथ अपने रिश्ते खराब करने वाला कोई कदम नहीं उठाया है।

बातचीत और कूटनीति के

जरिए समाधान : गोयल

पड़ोसी मुल्क से भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "हम कोई विस्तारवादी देश नहीं हैं। हमने हमेशा बातचीत, कूटनीति और दुनिया की समस्याओं का समाधान निकालने में विश्वास किया है। हम आगे भी वैश्विक स्तर पर विकास के लिए बातचीत और कूटनीति को अपने उपकरण के रूप में बनाए रखने और हर संभव कोशिश करना जारी रखेंगे। लेकिन अगर कोई आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो उसे भारत के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

अमेरिका को विश्वसनीय व्यापार भागीदार करार देते हुए गोयल ने वाशिंगटन डीसी में कहा, "सबसे पहले, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि भारत अमेरिका को अपना सबसे विश्वसनीय व्यापार भागीदारों में से एक के रूप में देखता है। अमेरिका के साथ हम सामानों, सेवाओं, टेक्नोलॉजी और निवेश जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों तथा व्यापार का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। हम दोनों के बीच रिश्ते को गहराई से महत्व देते हैं।" उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के तहत हमारे बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन प्रशासन के साथ बढ़िया संबंध रहे हैं। हम आगे भी संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने शानदार संबंधों को बनाए रखेंगे।" पीयूष गोयल अभी अमेरिका की यात्रा पर हैं। उन्होंने अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो के साथ व्यापार से जुड़े कई मसलों पर चर्चा की। साथ ही रायमोंडो के साथ छठे भारत-अमेरिका सीईओ मंच की सह-अध्यक्षता भी की।

इजराइली सेना का मध्य बेरूत में एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के 9 सदस्यों को उतारा मौत के घाट

यरुशलम, एजेंसी। इजराइल ने मध्य बेरूत की एक इमारत को निशाना बनाकर हवाई हमला किया, जिससे नौ लोगों की मौत हो गई. इन लोगों को हिजबुल्लाह का सदस्य बताया गया है. इजराइल सितंबर के अंत से ही लेबनान के उन क्षेत्रों पर बमबारी कर रहा है, जहां उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह की मजबूत उपस्थिति है. लेकिन राजधानी बेरूत के मध्य क्षेत्र को शायद ही कभी निशाना बनाया गया हो.

बुधवार देर रात हुए हमले से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, जिसमें मध्य बेरूत में एक इमारत को निशाना बनाया गया. यह इमारत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद से ज्यादा दूर नहीं है. वहीं, हिजबुल्ला की नागरिक सुरक्षा इकाई ने कहा कि उसके सात सदस्य मारे गये हैं. यह हमला दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के साथ झड़प में कम से कम आठ इजराइली सैनिकों के मारे जाने के बाद हुआ है. बेरूत में हमले के बाद निवासियों ने सल्फर जैसी गंध की शिकायत की जबकि लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बिना कोई सबूत दिए इजराइल पर फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

वहीं, इजराइल की सेना ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों के लोगों से जगह खाली करने की चेतावनी दी. यह क्षेत्र 2006 के युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित बफर जोन के उत्तर में स्थित है. इस चेतावनी से दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के संभावित विस्तार का संकेत मिलता है, जो अब तक सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित थी. इजराइल ने लोगों से प्रांतीय राजधानी नबातियेह से चले जाने को कहा.

ईरान के तेल संयंत्रों पर बढ़ा खतरा, बाइडन बोले- 'आज कुछ नहीं करेगा इजराइल'

ईरान। ईरान के इजराइल पर हमला करने बाद तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर 180 बैलेस्टिक मिसाइल दागी थीं। वहीं, अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें इसकी उम्मीद कम ही है कि इजराइल ईरान के खिलाफ तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा। वहीं बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इजराइल पर मिसाइल हमले के बदले के रूप में ईरान की तेल सुविधाओं पर हमले पर चर्चा कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल की सेना लेबनान में ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है। बता दें कि इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई ने इसे अल्लाह की दी हुई जीत बताया था। वहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। अमेरिका ने भी ईरानी हमलों की निंदा करते हुए अपने जंगी जहाजों को इजराइल की मदद के लिए तैनात किया था। इजराइल अपने कट्टर दुश्मन ईरान के हमले के बाद अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। वहीं जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या वह ईरान की तेल सुविधाओं पर हमला करने वाले इजराइल का समर्थन करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी टिप्पणियों ने वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि में योगदान दिया, और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने व्यापारियों को आपूर्ति व्यवधानों के बारे में चिंतित कर दिया है। जो बाइडेन ने कहा कि आज कुछ नहीं होने वाला है। राष्ट्रपति ने कहा कि वह ईरान के परमाणु स्थलों पर किसी भी इजराइली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। इजराइल के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत डैनी डैनन ने गुरुवार को सीएनएन को बताया कि उनके देश के पास जवाबी कार्रवाई के लिए बहुत सारे विकल्प हैं और वह तेहरान को जल्द ही अपनी ताकत दिखाएगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन को विश्वास नहीं है कि इजराइल ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि ईरान को कैसे जवाब देना है। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि ईरान मंगलवार के मिसाइल हमले के लिए भुगतान करेगा, और वाशिंगटन ने कहा कि वह अपने लंबे समय के सहयोगी के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि ईरान को गंभीर परिणाम का सामना करना पड़े।

चीन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को क्यों दे रहा है बढ़ावा, कहीं ये चाल तो नहीं?

बीजिंग। चीन प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन इसके पीछे उसकी गहरी चाल है। ऐसा दावा एक मीडिया रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वह कई साल से ऑटो निर्माता कंपनियों से कथित तौर पर कारों की लोकेशन का डाटा लेकर अपने पास इकट्ठा कर रहा है। इस बारे में कार मालिक को जरा भी खबर नहीं है। डाटा का कंट्रोल कई चीनी अधिकारियों और संस्थानों के पास है। बता दें कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता देश है।

द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार 200 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार मैन्युफैक्चरर चीनी सरकार समर्थित निगरानी केंद्रों को कार की लोकेशन का डाटा उपलब्ध करा रही हैं। 'द

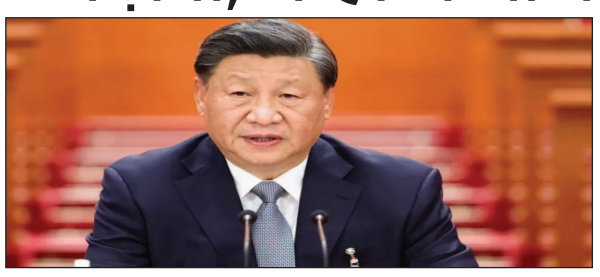

शंघाई इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक डाटा कलेक्टिंग, मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर' नामक रिपोर्ट एक समाचार एजेंसी के हाथ लगी है, जिससे चीन की जासूसी कराने के लिए तरीके का खुलासा हुआ है। चीन ने एक और रिपोर्ट तैयार कराई है जिसका नाम 'नेशनल बिग डाटा अलायंस ऑफ न्यू एनर्जी व्हीकल्स' है। इसमें भी कारों की लोकेशन का डाटा है।

चीनी अधिकारियों ने बताया कि यह डाटा पब्लिक सेफ्टी के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें कारों की रियल टाइम लोकेशन का डाटा है। साथ ही कई अन्य डाटा भी हैं। अधिकारियों ने डाटा इकट्ठा करने की एक और वजह यह बताई कि इसके जरिए सरकार की कोशिश धोखाधड़ी रोकना है। चीनी सरकार नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर काफी सब्सिडी भी दे रही है। यह डाटा 2017 से इकट्ठा किया जा रहा है। डाटा मोनिटरिंग केंद्र के स्टाफरों को हरेक कार का पूरा एक्सेस मिला हुआ है। वे किसी भी कंपनी की कार पर क्लिक कर उसका मेक, मॉडल, माइलेज और बैटरी चार्ज तक चेक कर लेते हैं। मर्सिडीज बेंज की पेरेंट कंपनी डायमलर ने कहा कि कंपनियां ट्रैकिंग का डाटा चीनी सरकार के साथ साझा कर रही हैं। फॉक्सवैगन की ओर से भी यही जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। फोर्ड ने इस बारे में टिप्पणी से इनकार किया है। निसान, बीएमडब्ल्यू और टेस्ला ने भी बयान देने से मना किया। कार कंपनियों का कहना है कि वे अपने कारोबार को चीन में बरकरार रखने के लिए ऐसा कर रही हैं।

कार निर्माता कंपनियों को चीन में कारोबार शुरू करने के लिए वहां की लोकल कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम लगाना होता है। तभी उन्हें चीन में कारोबार की मंजूरी मिलती है।

जासूसी का खतरा

चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों में लगे माइक्रोचिप्स और सेंसर्स के जरिए व्यापक पैमाने पर डेटा एकत्र किया जा सकता है।

• वाहनों में लगे सेंसर और चिप्स उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी एकत्र कर सकते हैं। • यह डेटा हजारों किलोमीटर दूर चीन के सर्वर में जमा हो सकता है। • चीन की खुफिया एजेंसियां इस डेटा तक आसानी से पहुंच सकती हैं।

• हैकर्स वाहन के नेविगेशन सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं। • बैटरी को ओवरहीट किया जा सकता है, जिससे जानलेवा दुर्घटना हो सकती है। • वाहनों को "चार पहियों वाले बम" में बदला जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने किया नई एसआईटी का गठन, सीबीआई और फस्सई के अधिकारी भी होंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। तिरुपति प्रसादम विवाद की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच के लिए नई पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। यानी राज्य की एसआईटी को कोर्ट ने खत्म कर दिया। अब इस मामले की जांच करने वाली नई एसआईटी में सीबीआई के दो अधिकारी होंगे। इसके अलावा टीम में दो लोग राज्य पुलिस से और एक अधिकारी FSSAI का होगा। कोर्ट ने ये आदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने पुरानी एसआईटी पर भरोसा जताया था, लेकिन कोर्ट ने नई एसआईटी का गठन कर दिया।

सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह राजनीतिक नाटक बने। स्वतंत्र निकाय होगा तो आत्मविश्वास रहेगा। कल यानी बुधवार को इस मामले की सुनवाई टल गई थी। एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि शुक्रवार को केंद्र का जवाब रखेंगे इसलिए इस मामले की सुनवाई एक दिन के टल गई थी।

पिछली सुनवाई में SC ने क्या कहा था?

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि क्या राज्य सरकार की एसआईटी काफी है या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपी जानी चाहिए। एसजी ने कहा कि मैंने मुद्दे पर गौर किया। एक बात साफ है कि अगर इस आरोप में सच्चाई का कोई अंश है तो यह अस्वीकार्य है। मुझे एसआईटी के सदस्यों के खिलाफ कुछ नहीं मिला।

एसजी ने कहा कि एसआईटी की निगरानी किसी वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारी द्वारा की जाए। यह विश्वास को बढ़ाएगा। जस्टिस गवई ने कहा कि हमने अखबार में पढ़ा है कि अगर जांच कराई जाए तो मुख्यमंत्री को कोई आपत्ति नहीं है। रोहतगी ने कहा कि हम एसआईटी के साथ जाना चाहते हैं। आपकी पसंद के किसी भी अधिकारी को शामिल कर सकते हैं। सरकार ने भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एफआईआर दर्ज की।

याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच हो तो यह उचित होगा। अगर उन्होंने बयान न दिया होता तो दूसरी बात होती। इसका प्रभाव पड़ता है। सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें मामले की जांच कर रही आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT के सदस्यों पर भरोसा है। SG ने कहा कि उनकी सलाह है कि SIT जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए।

क्या है तिरुपति लड्डू विवाद?

दरअसल, इस महीने की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि राज्य में पिछली सरकार (जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली) के दौरान तिरुपति में लड्डू तैयार करने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। नायडू के इस बयान के बाद बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में तीन से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गईं। याचिका दाखिल करने वालों में सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी और इतिहासकार विक्रम संपत शामिल हैं। 30 सितंबर को इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस मामले में कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखें।

योगी सरकार जब एक्शन ले तो रोना मत...अमेठी दलित हत्याकांड पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अमेठी दलित हत्याकांड पर दुख जताया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अमेठी में एक दलित परिवार के चार लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि अपराधियों में खौफ बना रहे।

इसके साथ ही मांझी ने पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी और अन्य उचित राहत मुहैया देने की भी मांग की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर लिया और कहा कि

जब योगी जी की सरकार एक्शन ले तो विलाप ना करें।

अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या

अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कातिलों ने मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। उसे भी मौत के घाट उतार दिया। कातिलों ने घर में घुसकर शिक्षक सुनिल कुमार, उनकी पत्नी पूनम और उनके दो मासूमों को गोलियों से भून दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, सुनील भारती को तीन गोलियां मारी गई थीं। वहीं, पूनम को दो गोलियां और दोनों बच्चों को एक-एक गोली मारी गई थी।

एक्स्ट्रा मैरिटेल अफेयर से जुड़ा है मामला

अमेठी दलित हत्याकांड मामले में पुलिस का कहना है कि दलित परिवार की हत्या का कनेक्शन एक्स्ट्रा मैरिटेल अफेयर से जुड़ा है। मृतक टीचर सुनील भारती की पत्नी पूनम का इस कांड़ के मुख्य आरोपी चंदन वर्मा के साथ अफेयर था। सुनील को भी इसकी जानकारी थी। सुनील ने उसे चंदन से दूर रहने को कहा था। पूनम ने चंदन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

अमेठी हत्याकांड का मुख्य आरोपी चंदन वर्मा का परिवार फरार है। उसके घर पर ताला लगा हुआ है। चंदन वर्मा रायबरेली का ही रहने वाला था। मृतक दलित परिवार भी रायबरेली का रहने वाला है।

दिल्ली के 5000 करोड़ ड्रग्स केस का असली मास्टरमाइंड वीरेंद्र बसोया, दुबई और यूके से कनेक्शन

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के 5000 करोड़ के ड्रग्स मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग सिंडिकेड के मास्टरमाइंड के तौर पर भारतीय नागरिक वीरेंद्र बसोया का नाम सामने आया है, जो दुबई में मौजूद है। पिछले साल पुणे पुलिस ने दिल्ली में छापेमारी कर जो 3000 करोड़ ड्रग्स (म्याऊं म्याऊं) पकड़ा था उस ड्रग्स सिंडिकेट में भी बसोया का नाम सामने आया था। पुणे पुलिस ने बसोया के दिल्ली के पिलंजी गांव में रेड भी की थी लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले ही वो भाग गया था। बसोया ने पिछले साल की यूपी के एक पूर्व विधायक की बेटी से अपने बेटे की शादी भी दिल्ली के एक शानदार फॉर्महाउस में की थी। अब इस 5 हजार करोड़ के ड्रग्स का मास्टरमाइंड भी उसे ही बताया जा रहा है। बसोया भारत मे ड्रग्स मामले में गिरफ्तार भी हो चुका है और जमानत मिलने के बाद दुबई शिफ्ट होकर इंटरनेशनल ड्रग्स कार्टेल का बड़ा माफिया बन गया। तुषार गोयल और बसोया पुराने दोस्त हैं और बसोया ने ही तुषार को ड्रग्स नेक्सेस में अपने साथ जोड़ा था। बसोया ने कोकीन की खेप की डिलिवरी के बदले 3 करोड़ हर एक कन्साईनेट तुषार को देने की डील की की थी। दुबई से बसोया ने इससिंडिकेट से जुड़े UK में मौजूद जितेन्द्र गिल को भारत जाने को कहा था, जिसके बाद यूके से तुषार से मिलने ड्रग्स डील के लिए जितेन्द्र गिल दिल्ली आया जहां तुषार उसे पंचशील इलाके के एक होटल मे रुकवाया फिर दोनों गाजियाबाद मॉल लेने गए और फिर हापुड़। मुंबई में जो कोकीन सप्लाई होना था उस शख्स की पहचान भी स्पेशल सेल ने की। बसोया लंबे वक्त से दुबई से कोकीन की डील से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इंटरनेशनल एजेंसियों को वीरेंद्रबसोया को लेकर इनपुट्स शेयर किए गए हैं ताकि उसे दुबई में दबोचा जा सके वीरेंद्र वसोवा के डी कंपनी लिंक भी खंगाले जा रहे हैं।

अवनीत कौर ने फिल्म लव इन वियतनाम का पहला शेड्यूल पूरा किया

अभिनेत्री अवनीत कौर ने अपनी फिल्म लव इन वियतनाम का पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी होने के बाद सेट से कुछ तस्वीरें साझा की।

इंस्टाग्राम पर अवनीत के 31.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपने कलाकारों और क्रू के सदस्यों के साथ तस्वीरों की एक श्रृंखला और खूबसूरत वियतनाम की कुछ झलकियां शेयर की।

उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, और यह लव इन वियतनाम (गुलाबी दिल वाली इमोजी के साथ) के पहले शेड्यूल का रैप है। जल्द ही सिनेमाघरों में आ रहा है (क्लैप-बोर्ड इमोजी के साथ)। मुझे इस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना और भारत-वियतनाम के सहयोग से बन रही पहली फिल्म का हिस्सा बनने पर बहुत गर्व है। अगले साल कान्स फिल्म फेस्टिवल में मिलते हैं।

पोस्ट में, अभिनेत्री कौर एक क्लैपरबोर्ड पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं, जिसके चारों ओर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो उनकी जिंदादिली को दर्शाती हैं। वियतनाम की खूबसूरती इनमें साफ छलक रही है और अवनीत क्रू के साथ बेहद खुश नजर आ रही हैं।

अवनीत के लुक की फैंस ने प्रशंसा की है। एक फैन ने लिखा, हम सभी को बहुत-बहुत बधाई। हम बहुत खुश हैं कि आप इस ऐतिहासिक परियोजना का हिस्सा हैं। और केवल कान्स ही नहीं... हम अगले साल दुनिया को हिलाकर रख देंगे। एक अन्य यूजर ने लिखा, आपको टीवी स्क्रीन पर देखने से लेकर कान्स फ्लोर पर आपको देखना मेरे लिए वास्तव में गर्व की बात है!!! मैं आपके लिए बहुत बहुत बहुत खुश हूं अवु दीदी!!! मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और सम्मान। लव इन वियतनाम फिल्म बेस्टसेलर मैडोना इन ए फर कोट पर आधारित है, फिल्म में शांतनु और वियतनामी अभिनेत्री खा नगन भी हैं, निर्देशन राहत शाह काज़मी ने किया है और इसका निर्माण ओमंग कुमार ने किया है। अवनीत ने साल 2010 में जी टीवी के डांस शो डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स से मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने 2012 में लाइफ ओके के शो मेरी मां से एक्टिंग में डेब्यू किया।

इसके बाद अभिनेत्री सब टीवी के टेढ़े हैं पर तेरे मेरे हैं में नजर आईं। उन्होंने तारे जमीन पर फेम अभिनेता दर्शील सफारी के साथ सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 5 में भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा, वह मर्दानी, चिडिय़ाखाना, टीकू वेड्स शेरू और लव की अरेंज मैरिज जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं।

विजय की आखिरी फिल्म थलापति 69 से आया बड़ा अपडेट, बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल की हुई एंट्री

थलापति 69 साउथ सुपरस्टार विजय की आखिरी फिल्म हो सकती है इसीलिए फैंस इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं। इसी के साथ मेकर्स भी आए दिन फिल्म से नया अपडेट शेयर करते हुए फैंस की एक्साइटमेंट बरकरार रख रहे हैं। इसी बीच मेकर्स ने फिल्म की कास्ट रिवील की है। तो आइए जानते हैं थलापति की फिल्म में किस बॉलीवुड एक्टर ने एंट्री ली है।

थलापति 69 के मेकर्स ने बड़ा अपडेट शेयर करते हुए बताया कि फिल्म में बॉबी देओल की एंट्री हो चुकी है। हालांकि उनका रोल क्या होगा अभी इस बारे में खुलासा नहीं हुआ है। केवीएन प्रोडक्शन ने हाल ही में एक धांसू पोस्टर शेयर किया जिसमें बॉबी देओल का फेस रिवील किया गया। पोस्टर के साथ मेकर्स ने कैप्शन लिखा- 100त्न ऑफिशियल, हम बहुत खुश और एक्साइटेड हैं अनाउंस करते हुए कि बॉबी देओल ने थलापति 69 की कास्ट जॉइन कर ली है।

थलापति 69 में बॉबी देओल की एंट्री से फैंस काफी खुश हो गए हैं सबने कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी जाहिर की। एक ने लिखा- वाह थलापति विजय और बॉबी देओल, स्क्रीन पर धमाका होगा। एक ने कमेंट किया- वाव बड़े पर्दे पर धमाका होगा। एक ने लिखा-थलापति का लुक कब सामने आएगा, अब इंतजार नहीं हो रहा। केवीएन प्रोडक्शंस ने थलापति 69 को प्रोड्यूस किया है जिसे तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया जाएगा। प्रोडक्शन हाउस ने हाल ही में फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया और टैगलाइन के साथ इसकी डिटेल की अनाउंसमेंट की। उन्होंने कैप्शन में लिखा- द टॉर्च बैरियर ऑफ डेमोक्रेसी। हमें यह अनाउंस करते हुए बहुत गर्व और एक्साइटमेंट हो रहा है कि हमारी पहली तमिल

फिल्म थलपति 69 है, जिसका निर्देशन दूरदर्शी एच विनोथ ने किया है और म्यूजिक रॉकस्टार अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है। थलपति विजय के साथ कोलेब करके बहुत खुशी हुई। द टॉर्च बेरियर ऑफ डेमोक्रेसी अक्टूबर 2025 में आ रहे हैं।

उनकी पॉलीटिकल पार्टी का नाम तमिलगा वेत्री कझगम है।वर्कफ्रंट की बात करें तो फिलहाल विजय अपनी हालिया रिलीज फिल्म गोट की सफलता का आनंद ले रहे हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग की थी। वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 200 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर ली है। वहीं चर्चा है कि विजय थलापति 69 के बाद सिर्फ अपने पॉलीटिकल करियर पर फोकस करेंगे।

कोंडा सुरेखा के विवादित बोल पर राम चरण ने दी प्रतिक्रिया, बताया गैर-जिम्मेदार और निराधार बयान

सामंथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्या को लेकर कोंडा सुरेखा की चौंकाने वाली टिप्पणियों पर विवाद जारी है। सुरेखा के इस टिप्पणी के बाद कई सितारों ने इसका खुलकर विरोध किया और आपत्ति जताई है। इस बीच अब अभिनेता राम चरण अपने रंगस्थलम की सह-कलाकार सामंथा और अक्किनेनी परिवार के समर्थन में सामने आए हैं। अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर, राम चरण ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए तेलंगाना के मंत्री की टिप्पणियों की आलोचना की है।

राम चरण ने अपने पोस्ट मे लिखा, 'कोंडा सुरेखा गरु द्वारा दिए गए बयान गैर-जिम्मेदार और निराधार हैं। सम्मानित व्यक्तियों के बारे में इस तरह की भद्दी सार्वजनिक टिप्पणी करना चौंकाने वाला है, खासकर एक निर्वाचित नेता द्वारा जो सार्वजनिक पद पर है। इस तरह की बदनामी का उद्देश्य हमारे समाज की बुनियादी बातों को नष्ट करना है।' उन्होंने आगे कहा कि फिल्म उद्योग इस तरह के लापरवाह व्यवहार के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने कहा, ₹फिल्म बिरादरी एक साथ है और हमारे खिलाफ इस तरह के लापरवाह व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा निजी जीवन हमारे लिए काफी पवित्र है और उचित सम्मान का हकदार है। हम सार्वजनिक हस्ती हैं, हमें एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए, न कि एक-दूसरे को तोड़ना चाहिए।'

साउथ के कई सितारों ने की सुरेखा की आलोचना

सुरेखा द्वारा इस विवादित और अशोभनीय टिप्पणी को लेकर तेलुगु फिल्म उद्योग ने सामंथा और अक्किनेनी परिवार का समर्थन किया है। राम चरण के अलावा दक्षिण भारत के अन्य प्रमुख सितारों ने भी अक्किनेनी परिवार के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। जूनियर एनटीआर, विजय देवरकोंडा, अल्लू अर्जुन, एसएस राजामौली और चिरंजीवी जैसी हस्तियों ने सामंथा, नागा चैतन्य और अक्किनेनी परिवार के साथ अपना समर्थन जाहिर किया है। इसके साथ ही सभी सितारों ने एक स्वर में कोंडा सुरेखा द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों की निंदा की है।

कोंडा सुरेखा की विवादास्पद टिप्पणी

बता दें कि विवाद तब शुरू हुआ जब कोंडा सुरेखा ने दावा किया कि एक अन्य प्रमुख राजनेता केटी रामा राव ने नागार्जुन के एन-कन्वेंशन सेंटर के संबंध में सामंथा को लेकर कथित तौर पर अनुचित मांग की थी। सुरेखा के बयान की काफी आलोचना हुई, जिसके बाद भारी विरोध के कारण उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। हालांकि, तब तक उनका बयान सुर्खियां बटोर चुका था। इसके बाद नागार्जुन अक्किनेनी ने कोंडा सुरेखा के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया। उन्होंने इस आरोप को हास्यापद बताते हुए कहा कि नागा चैतन्या और सामंथा का तलाक आपसी सहमति से हुआ था।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com